RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

मासिक, बलौदाबाजार से प्रकाशित

वर्ष : 03 अंक : 04 मासिक, बलौदाबाजार,अप्रैल 2024 E-mail: newsroutine6@gmail.com पृष्ठ : 16 मूल्य : 15 रू.

जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं?

मोदी ने लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया

बस्तर रैली में पीएम का कांग्रेस पर प्रहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर पहुंचे. उन्होंने यहां कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया है. इस बार भी बस्तर समेत पूरे प्रदेश के मेरे परिवारजन सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का मन बना चुके हैं. इस मौके पर पीएम मोदी ने छत्तसीगढ़ के वरिष्ठ नेता स्व. बलिराम कश्यप को याद किया. उन्होने कहा कि आदिवासी के कल्याण के लिए बलिराम कश्यप हमेशा जागरूक रहते थे. बलिराम कश्यप ने अपना आर्शीवाद देने में कभी कमी नहीं की. पिछले 10 साल में देश ने जो प्रगति की है उसमें आपका सहयोग मिला है. आपने सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला रखी है. आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब का कल्याण रही है. कांग्रेस ने गरीबों की परेशानियों को समझा ही नहीं. 2014 में जनता ने गरीब के बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया. जब घर में राशन नहीं होता तो मां पर क्या बीतती है मुझे पता है. दवा खरीदने के पैसे घर में नहीं होते तो बेबसी क्या होती है, ये मैं जानता हूं. जब तक गरीबों की परेशानियां दूर नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा. 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं.

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बस्तर संभाग से मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरूआत की थी. आने वाले 5 साल मोदी मुफ्त राशन की सेवा करता रहेगा. बचा हुआ पैसा सपने पूरा करने के काम आता है. कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गई थी. भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता है. साल 2014 से पहले लाखों करोड़ के घोटाले होते थे. दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और गांव तक 15 पैसे पहुंचते थे. ये बात कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने ही बोली थी. वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था.

मोदी धमकियों से डरने वाला नहीं है- पीएम

मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं. मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रखकर चलता है. मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है. मोदी के लिए मेरा भारत मेरा परिवार है. मैं अपने देश को अपने परिवार को लूट से बचाने में जुटा हूं. मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ. मोदी ने लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया.

कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामलाल टेंट पर नहीं, मंदिर से रामनवमी को दर्शन देंगे. कांग्रेस राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है. कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया दिया. कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है. कांग्रेस के घोषणापत्र में मुस्लिम लीग की छाप है. बीजेपी ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी सीएम दिया है. आपका सपना ही मोदी का संकल्प है. हर पल देश के नाम. जिसको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूजा है.

बस्तर में राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना

70 करोड़ भारतीयों से ज़्यादा संपत्ति मोदी जी के 22 अमीरों के पास...

जगदलपुर। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है. सभी पार्टियों के नेता लगातार अलग-अलग प्रदेशों में जाकर रैलियां और जनसभा कर रहे हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया. राहुल गांधी ने कहा, 'इस बार के चुनाव में आपके सामने दो विचारधारा की लड़ाई है. पहली संविधान को बचाने वाली यानि कांग्रेस और दूसरी बीजेपी जो संविधान खत्म करना चाहती है।'

पीएम मोदी केवल अरबपतियों की मदद करते

केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'लाखों लोग कोरोने के कारण मरे, हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटेज्केंद्र की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, किसी की भी मदद नहीं की. प्रधानमंत्री मोदी पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं. भारत में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है, जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है. पीएम मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं.'

जंगलों को खत्म कर रही बीजेपी

बस्तर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहती है, उनको उनके अधिकारों से दूर रखती है. आदिवासियों का सबसे पहला हक जल, जंगल और जमीन है और आरएसएस के लोगों ने उनका हक छीना है. भाजपा जंगल को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जब जंगल ही नहीं रहेगा तो आदिवासी कहां जाएंगे ? नेता ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका हक दिया है.

सत्ता में आएंगे तो बेरोज़गारों कौ नौकरी देंगे

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अगर जनता हमारी सरकार को मौका देगी तो हम देश के सब बेरोज़गार युवाओं को ये अधिकार देंगे कि वह एक साल के लिए निजी कंपनी में, PSUs में, सरकारी कार्यालयों में नौकरी कर सकेंगे, जिसमें उनका प्रशिक्षण होगा और 1 साल में उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने कहा अगर युवा अच्छा काम करेंगे तो उन्हीं संस्थाओं में उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी.

ईवीएम के विश्ववसनीयता पर संदेह निराधार,

सुरक्षा मानकों से चलती है ईवीएम

रायपुर। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने एक दिवसीय उन्मुखीकरण और कार्यशाला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब ईवीएम को लेकर कोई संदेह नहीं है। इस पर उठने वाली शंकाएं निराधार है। इसके संचालन के लिए निश्चित प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, जो पूर्ण रूप से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होता है। पत्रकार निर्वाचन के दौरान अन्य विभागों के साथ ही अति आवश्यक सेवा में होते हैं। ऐसे में मतदाता के तौर पर कर्तव्य पूरा करने के लिए डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देश पर रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित मीडिया कार्यशाला में निर्वाचन संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इलेक्शन मशीनरी और इसमें लगे अधिकारियों-कर्मचारियों की विशेषज्ञता और निष्पक्षता संदेह से परे है। इस दौरान सभी को भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल्स और मोबाइल एप की जानकारी दी। सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शारदा अग्रवाल ने

पेड न्यूज, मीडिया मॉनिटरिंग सेल, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के कामों के बारे में बताया।

इस दौरान सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यूएस अग्रवाल ने ईवीएम की कार्यप्रणाली का उल्लेख किया। उन्होंने इसकी सुरक्षा में बरती जाने वाली सावधानियां और पारदर्शी प्रणाली की जानकारी दी।

पहले कांग्रेस अब बीजेपी का बना गढ़

राजनांदगांव लोकसभा-मैदान में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, करा पाएंगे पंजे की वापसी

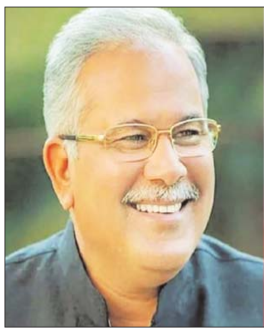

देश के 543 और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र में से एक राजनांदगांव लोकसभा सीट सूबे की एक प्रमुख वीआईपी सीट है. एक तरफ जहां इसबार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी ने यहां अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा है. राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह विधायक चुने गए हैं. इसलिए भी यह सीट खास हो जाता है. 2024 में छत्तीसगढ़ हाई प्रोफाइल सीट बनने जा रहा है और यहां मुकाबल दिलचस्प होने के आसार हैं. चुनाव परिणाम के दिन सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई रहेगी. बीजेपी के संतोष पांडे अभी राजनांदगांव को सांसद हैं. बीजेपी यहां लगातार चार बार जीत दर्ज कर चुकी है.

संतोष पांडे ने 2019 में कांग्रेस पार्टी के भोला राम साहू को हराया है. पांडे को जहां 50.68 प्रतिशत मत मिले थे वहीं कांग्रेस के भोला राम साहू को 42.11 वोट मिले. तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रविता लाकड़ा को 1.31 प्रतिशत वोट मिले थे.

भोला राम साहू को हराया

बीजेपी उम्मीदवार संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोला राम साहू को 1,11,966 वोटों से हराया था. बीजेपी के संतोष पांडे को जहां 662,387 वोट मिले थे वहीं कांग्रेस पार्टी के भोला राम साहू को 5,50,421 वोट जबकि तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के रविता लाकड़ा (ध्रुव)को महज 17,145 वोट मिले थे. बीएसपी उम्मीदवार रविता लाकड़ा को नोटा 19,436 से भी कम वोट मिले थे.

2014 में बीजेपी के दूसरी जीत

इससे पहले 2014 में बीजेपी के अभिषेक सिंह ने कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,35,911 वोटों से हराया था. अभिषेक सिंह को जहां 6,43,473 वोट मिले वहीं कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 4,07,562 वोट. तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के आनंद साहू को 20,458 वोट मिले थे. चौथे स्थान पर 20,458 नरेंद्र बंसोड़ को 11704 वोट मिले.तीसरे और चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवार को नोटा के 32,385 वोट से कम वोट मिले थे.

राजनांदगांव का चुनावी इतिहास

राजनांदगांव में 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राजा बहादुर सिंह ने जीत दर्ज की थी. राजा बहादुर सिंह 1962 में कांग्रेस की टिकट पर संसद पहुंचे.1967 में कांग्रेस की पद्मावती देवी और 1971 में रामसहाय पांडे ने जीत हासिल की. 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी के मदन जीत दर्ज करने में कामयाब हुए. इसके बाद 1980 और 1984 में कांग्रेस के शिवेंद्र बहादुर सिंह जीत दर्ज करने में कामयाब हुए. 1989 में धर्मपाल सिंह गुप्ता ने बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की. 1991 में एकबारशिवेंद्र बहादुर सिंह सांसद बने. 1996 में बीजेपी के अशोक शर्मा, 1998 कांग्रेस के मोतीलाल बोरा. 1999 में बीजेपी के डॉ. रमन सिंह. 2004 में बीजेपी के प्रदीप गांधी, 2009 में बीजेपी के मधुसूदन यादव ने जीत दर्ज की.

राजनांदगांव का वोट गणित

राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र आठ विधानसभा- डोंगरगांव, मोहला-मानपुर, डोंगरगढ़, खैरागढ़, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा और राजनांदगांव है. राजनांदगांव में कुल 17,16,459 मतदाता है. इनमें 8,57,304 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,59,149 है. यहां थर्ड जेंडर निर्वाचक 6 है. 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां कुल मतदान प्रतिशत-76.15था. बात जातिगत समीकरण की करें तो राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछड़ा व के वोटर निर्णायक है वहीं साहू समाज के भी वोट भी जीत हार तय कर सकते हैं. साहू समाज के करीब 5 लाख से ज्यादा वोटर हैं.

मां बम्लेश्वरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर

राजनांदगांव का इतिहास गौरवशाली रहा है. इसे छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहा जाता है. यहां स्थित एशिया का पहला और एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विवि के नाम से खैरागढ़ की पूरी दुनिया में विशेष पहचान है. डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है।

2 हजार करोड़ के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द,

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द कर दिया है। दो हजार करोड़ के शराब घोटाले केस में सभी 6 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से बड़ी राहत दी है। इस केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

जस्टिस अभय एस औका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले में टिप्पणी करने के बाद शिकायत को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के अनुसार अपराध नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि मामले में ईसीआईआर और एफआईआर को देखने से पता चलता है कि कोई विधेय या अपराध नहीं हुए हैं। सवोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब कोई आपराधिक धनराशि ही नहीं है तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं बनता है।

जानें क्या है दो हजार करोड़ का शराब घोटाला

ईडी की जांच के मुताबिक, पूर्व कांग्रेस सरकार में उच्च स्तरीय अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राजनीतिक अधिकारियों वाला एक सिंडिकेट काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ में शराब व्यापार में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। साल 2019-22 में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक काले धन की कमाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2022 में दिल्ली की एक अदालत में दायर आयकर विभाग की चार्जशीट से उपजा है। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई। प्रति शराब मामले के आधार पर राज्य में डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई और देशी शराब को ऑफ-द-बुक बेचा गया। ईडी के मुताबिक, डिस्टिलर्स से कार्टेल बनाने और बाजार में एक निश्चित हिस्सेदारी की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली गई थी।

जनवरी 2024 में हुई थी एफआईआर

एसीबी और ईओडब्ल्यू ने ईडी के पत्र के आधार पर जनवरी 2024 में एफआईआर दर्ज की है।ईओडब्ल्यू के दर्ज एफआईआर में अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर को शराब घोटाला का मास्टरमाइंड बताया गया है। एफआईआर में शामिल बाकी आईएएस और अन्य सरकारी ऑफिसर और लोग सहयोग किये थे। शराब घोटाला से होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं तीनों को जाता था। टुटेजा आईएएस ऑफिसर हैं, जब घोटाला हुआ तब वे वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव थे। दूरसंचार सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए त्रिपाठी आबकारी विभाग के विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के एमडी थे। वहीं अनवर ढेबर रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई और शराब कारोबारी है।

पीएचई एसडीओ डेढ़ लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

राजनांदगांव। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजेश मरावे ने ठेकेदार का बिल भुगतान करने की एवज में डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी।

ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। एसीबी ने 12 सदस्यों की टीम गठित की। गुरुवार की दोपहर सहायक अभियंता को उनके कार्यालय से ही रंगे हाथ दबोच लिया। मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार भुगतान नहीं होने से परेशान था। उसे 17 लाख का भुगतान किया जाना था। एसीबी के अधिकारी चार से पांच गाड़ियों में पहुंचे हुए थे।

तीन हजार की रिश्वत लेते पटवारी पकड़ाया

इधर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सूरजपुर के रामानुजनगर तेलईमुड़ा के पटवारी रामगोपाल साहू को स्टेट बैंक

ठेकेदार का बिल भुगतान करने की एवज में डेढ़ लाख रुपये की मांग की थी

सूरजपुर के बाहर एक ग्रामीण से तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर जेल भेज दिया है। पटवारी ने फौती चढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी।

आरोपित पटवारी पिउरी चौक रामानुजनगर का रहने वाला है। गोविंदपुर निवासी सुनील सिंह ने उप पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसकी पैतृक भूमि उसके माता-पिता के नाम से दर्ज है।

पिता के देहांत के बाद जब पटवारी रामगोपाल साहू से फौती चढ़ाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कराने के लिए गए तो उसने पांच से 10 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। एसीबी ने जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया। पटवारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, (यथा संशोधन 2018) के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

कांग्रेस का किला रहा महासमुंद, 11 बार मिली जीत,

अब भाजपा कर रही चौका मारने की तैयारी

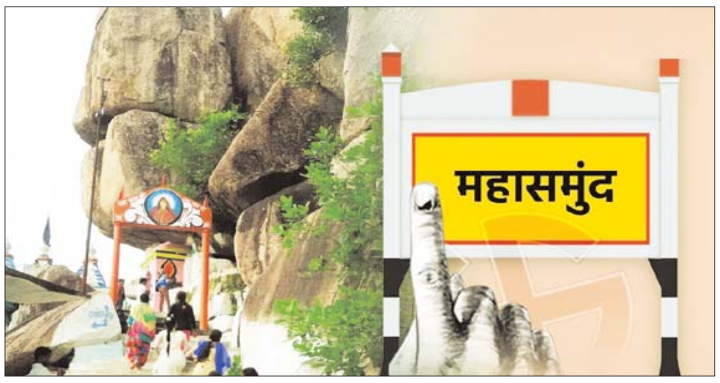

देश के 543 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक महासमुंद लोकसभा सीट है. महासमुंद छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है. यहां से विद्याचरण शुक्ल 6 बार सांसद चुने गए. वो एक बार यहां से जनता दल की टिकट पर भी संसद पहुंचे हैं. विद्याचरण शुक्ल के भाई एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्यामाचरण शुक्ल भी यहां से एक बार सांसद चुने गए हैं. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पहले सीएम रहे अजीत जोगी भी महासमुंद के सांसद रहे हैं. महासमुंद में 19 बार हुए लोकसभा चुनाव (उपचुनाव समेत) में कांग्रेस पार्टी ने 12 बार जीत दर्ज की है. कभी कांग्रेस का किला कहे जाने वाले महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में पिछले तीन बार से बीजेपी का कब्जा है. वर्तमान में यहां से चुन्नी लाल साहू सांसद हैं.

चुन्नी लाल साहू ने कांग्रेस पार्टी के धनेन्द्र साहू को हराया है. चुन्नी लाल साहू को जहां 50.44 प्रतिशत वोट मिले वहीं कांग्रेस के धनेन्द्र साहू को 43 प्रतिशत. यहां तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय देवेन्द्र सिंह ठाकुर को 1.27 प्रतिशत वोट मिले थे. जबकि चौथे स्थान पर रहे बीएसपी के धनसिंह कोसरिया को 0.92 प्रतिशत वोट ही मिले.

2019 में बीजेपी की तीसरी जीत

बीजेपी के चुन्नी लाल साहू ने कांग्रेस पार्टी के धनेन्द्र साहू को 90,511 वोटों से हराया था. चुन्नी लाल साहू को जहां 616,580 वोट मिले वहीं कांग्रेस के धनेन्द्र साहू को 5,26,069 वोट, तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय देवेन्द्र सिंह ठाकुर को 43.06 प्रतिशत मत मिले थे. जबकि चौथे स्थान पर रहे बीएसपी प्रत्याशी धनसिंह कोसरिया को 11245 वोट मिले. तीसरे और चौथे स्थान पर रहे प्रत्याशी को नोटा 21241 से भी कम वोट मिले थे.

2014 में भी जीती थी बीजेपी

इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां चंदूलाल साहू ने कांग्रेस पार्टी के अजीत जोगी को एक कड़े मुकाबले में 1,217 वोटों से हराया था. यहां तीसरे चौथे और पांचवे स्थान पर भी चंदूलाल साहू नाम के उम्मीदवार थे. तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय चंदूलाल साहू को 20255, चौथे स्थान के चंदूलाल साहू को 12308 और पांचवे स्थान पर रहे चंदूलाल साहू को 10979 वोट मिले थे. दरअसल 2014 में बीजेपी के चंदूलाल साहू के साथ यहां 11 चंदूलाल साहू ने नामांकन किया था. कहा जाता है कि अजीत जोगी ने सभी निर्दलीय चंदूलाल साहू को बीजेपी के चंदूलाल साहू को हराने के लिए मैदान में उतारा था.

महासमुंद का चुनावी इतिहास

महासमुंद में हुए पहले 6 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी. यहां 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के श्योदास डागा ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद 1957 में मगनलाल राधाकिशन बागड़ी, 1962, 1964 और 1967 में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी के विद्याचरण शुक्ल सांसद बने. 1971 में कांग्रेस के कृष्णा अग्रवाल, 1977 में जनता पार्टी के बृज लाल वर्मा, 1980, 1984 और 1989 में विद्याचरण शुक्ल ने लगातार तीन बार जीत दर्ज की. 1980 और 1984 में शुक्ला ने कांग्रेस जबकि 1989 में विद्याचरण शुक्ल ने जनता दल की टिकट पर जीत दर्ज की थी. 1991 और 1996 में बीजेपी के पवन दीवान ने जीत दर्ज की. 1998 में बीजेपी के चन्द्रशेखर साहू, 1999 में कांग्रेस के श्यामाचरण शुक्ल. 2004 में कांग्रेस के अजीत जोगी, 2009 में बीजेपी के चंदूलाल साहू यहां के सांसद बने.

महासमुंद का वोट गणित

महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा-धमतरी, खल्लारी, सरायपाली कुरूद, बसना, धमतरी, राजिम और महासमुंद सीट है. महासमुंध लोकसभा तीन जिले-धमतरी ,गरियाबंद और महासमुंद में विस्तारित है. यहां कुल 16,37,951 मतदाता हैं जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या-8,24,241 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,13,688 थर्ड जेंडर निर्वाचक 22 हैं. जातिगत समीकरण की बात करें तो महासमुंद में कुर्मी, अघरिया , यादव , कोलता वोटर की बहुलता है. यहां अनुसूचित जनजाति लगभग 20% , अनुसूचित जाति लगभग 11% है. इस लोकसभा क्षेत्र में 51% प्रतिशत मततदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं. बीजेपी ने 2024 में यहां रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताम्रध्वज साहू मैदान में हैं.

कुंड श्वेत गंगा बेहद लोकप्रिय स्थान

महानदी तट पर बसे महासमुंद संसदीय क्षेत्र की विशेष पहचान अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल सिरपुर और गंगरेल बांध है. दक्षिण कौशल की राजधानी रहे श्रीपुर सिरपुर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की मांग लगातार होती रही है. यहां के मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं. बम्हनी गांव में निरंतर प्रवाह होने वाली कुंड श्वेत गंगा लोकप्रिय स्थान है.

झूठ का व्यापार करती है कांग्रेस

खैरागढ़ सभा में गरजे शाह, बोले-नक्सलवाद को खत्म करने का किया दावा

राजनांदगांव। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राजनांगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय के समर्थन में रविवार को खैरागढ़ के फतेह मैदान में जमकर गरजे।

अमित शाह ने कहा, कांग्रेस झूठ बोलने से बाज नहीं आती है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बोलते हैं, पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की जनता से कहने आया हूं, आरक्षण को कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण दलितों की हो या आरक्षण पिछड़े वर्ग की हो।

शाह ने कहा, मोदी की तीसरी पारी में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का काम करेंगे। पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हो गया है। देश की पूंछ छत्तीसगढ़ में बाकी है। उसे भी इस बार खत्म करेंगे। पीएम मोदी की सरकार तीसरी बार बनवाइए, हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे।

अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव उम्मीदवार भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, भूपेश कका इतना सारा भ्रष्टाचार करके पेट नहीं भरा है अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। मैं आज राजनंदगांव की जनता को कहने आया हूं कि आप लोगों ने भूपेश बघेल को विधानसभा में हराया है, इससे भी बड़े मार्जिन के साथ इनको फिर से घर पर भेजने का काम करिए। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन नहीं किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया।छत्तीसगढ़ के बेटे-बेटियों को सट्टे का लत लगाने वाले भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको इस चुनाव में मजा चखाना है।

उधर अप्रैल के तीसरे सप्ताह में कांग्रेस भी बड़ी सभा कराने की तैयारी में है। चर्चा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा व छग प्रभारी सचिन पायलट की सभा हो सकती है। हालांकि संगठन के पास अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं पहुंचा है।

राजनांदगांव सीट से भाजपा उम्मीदवार संतोष पांडेय ने भरा पर्चा

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह सहित दिग्गज नेता मौजूद रहे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने संतोष पांडेय की जीत का दावा किया। सीएम साय ने कहा, आज राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र से संतोष पांडेय ने पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। वे आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। नामांकन से पहले सीएम साय ने शिवनाथ वाटिका में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पांच साल पहले मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस ने पांच साल में छत्तीसगढ़ को लूट लिया। छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया। आज वही ठगेश राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम कुछ नहीं है। केवल गाली देना जानते है। दो दिन पहले इसी राजनांदगांव में कांग्रेस की चुनावी सभा हुई जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी से मारने की बात कही गई।

संपादकीय

चुनाव में भाषा का संयम एवं वचनों की मर्यादा जरूरी

लोकसभा चुनावों जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, कई नेताओं की जुबान फिसलती जा रही है, वे राजनीति से इतर नेताओं की निजी ज़िंदगियों में तांक-झांक वाले, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ऐसे बोल बोल रहे हैं, जो न सिर्फ़ आपत्तिजनक हैं, बल्कि राष्ट्र-तोड़क है। चुनावी रैलियों में जनता के सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने के मकसद से ये नेता मर्यादा, शालीनता और नैतिकता की रेखाएं पार करते नज़र आए हैं। गलत का विरोध खुलकर हो, राष्ट्र-निर्माण के लिये अपनी बात कही जाये, अपने चुनावी मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाये, लेकिन गलत, उच्छृंखल एवं अनुशासनहीन बयानों की राजनीति से बचना चाहिए। बड़ा सवाल है कि एक ऊर्जावान एवं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या वाकई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल औचित्यपूर्ण है? चुनाव की तारीख तय होने एवं चुनावी पारा बढ़ने के बाद नेताओं के बयानों में तीखापन एवं हल्कापन आ गया है। एक तरफ गर्मी चुभन का अहसास करा रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में भाषायी अभद्रता एवं उच्छृंखलता घाव पर नमक छिड़क रही है। नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि सही तरीके से बोले गए शब्दों में लोगों को जोड़ने की ताकत होती है, जबकि गलत भाषा एवं बोल का इस्तेमाल राजनीतिक धरातल को कमजोर करता है।

हमारे देश की राजनीति में संयमित भाषा एवं अनुशासित बोल-बयान एक महत्वपूर्ण अंग होती है। लोकतंत्र में उसी नेता का बोल-बाला होता है, जिसकी भाषा एवं वचनों पर पकड़ मजबूत होती है। आजादी के बाद देश में जिस प्रकार राजनीति में बदलाव आता गया, उसी प्रकार राजनेताओं की भाषा और आरोप-प्रत्यारोप की शैली भी बदलती गई। आज कुछ राजनीतिक दलों के नेता अपने विपक्षी राजनेता को 'पप्पू' जैसे शब्दों से ताना मारते हैं, तो कोई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिये चौकीदार चोर है या चायवाला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हमारे देश की राजनीति में मर्यादा नाम का कोई शब्द बचा है? ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने से पहले हमारे ये राजनेता जरा भी नहीं सोचते कि उसका उनकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

मतदाताओं को आकर्षित एवं अपने पक्ष में करने के फेर में राजनीति को रसातल में धकेलने की मानो होड़ मची हुई है। क्षणिक रोमांच एवं तत्काल चुनावी लाभ के लिए मर्यादा को तार-तार करने वाले इन नेताओं को आत्म-चिंतन की सख्त जरूरत है।

समय प्रबंधन का महत्तव समझें

डा. वरिंदर भाटिया

पहली बात यह समझ लेनी है कि हमें समय का प्रबंधन नहीं करना है, बल्कि उपलब्ध समय के अनुसार अपना प्रबंधन करना है। दूसरी बात यह समझ लेनी चाहिए कि सीमित समय में आप जितने काम कर लेना चाहते हैं, वे कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे, इसलिए एक तरह के अधूरेपन को झेलने की, उसके साथ जीने की आदत आपको विकसित करनी ही होगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप एक साथ बहुत कुछ साधने की कोशिश करेंगे, तो पूरा खतरा है कि आप कुछ भी नहीं साध पाएंगे। जब तक आपके प्रयास 'फोकस्ड' नहीं होंगे, तब तक सफलता आपके नजदीक भी नहीं फटकेगी। कहा भी गया है कि 'एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाय'

एक शिक्षक होने के नाते और शैक्षिक प्रबंधन में एक लंबा अनुभव हासिल करने के बाद मैंने पाया कि टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन ठीक न होने के कारण मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इस बिंदु पर बात करना वृहद सामाजिक हित में महसूस हो रहा है। अगर आप दुनिया का इतिहास टटोलेंगे तो आपको कुछ ऐसे उदाहरण जरूर मिल जाएंगे जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने बहुत कम समय दिया, किंतु उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बाकी लोग उनकी तुलना में पर्याप्त समय होने के बाद भी नहीं कर सके। शहीद भगत सिंह जी 23 वर्ष की उम्र में कई गहरी किताबें लिखकर देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए, जबकि अधिकांश नौजवान इस उम्र तक यह भी तय नहीं कर पाते कि उनको जीवन में क्या करना है। शंकराचार्य जी को सिर्फ 32 वर्षों का जीवन मिला, किंतु वे उसी अवधि में अद्वैत वेदांत की ऐसी व्याख्या कर गए जिसे खारिज करने में बाकी दार्शनिक खुद को आज तक असमर्थ पाते हैं। पश्चिम के प्रसिद्ध रोमांटिक कवि कीट्स को सिर्फ 25 साल की जिंदगी मिली तो शेली को सिर्फ 29 साल की, पर तब भी अंग्रेजी की रोमांटिक कविता में जितना सम्मान इन कवियों को मिलता है, उतना पूरी शताब्दी जीने वालों को भी नहीं। सार यह है कि कुछ बड़ा करने के लिए बहुत लंबी जिंदगी की जरूरत नहीं होती, जिंदगी के एक-एक क्षण को ठीक से जीने और निचोड़ लेने की जरूरत होती है। ऐसे और भी हजारों उदाहरण हैं। मैं कुछ ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने कोई नौकरी करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और इसके बावजूद सफलता हासिल की, जबकि दूसरी ओर ऐसे हजारों उम्मीदवार हैं जिन्हें उनके घर से बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं, बिना किसी तनाव के 24 घंटे पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन तब भी उनकी सफलता दर उन लोगों से कम दिखती है जो नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि नौकरी करने वाले व्यक्तियों को एक-एक क्षण की कीमत का एहसास होता है।

कई लोगों के साथ यह परेशानी होती है कि वे कुछ काम करने की सोचते हैं, दिन के खत्म होने तक वो बहुत से काम करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं जिसके बारे में वे सोचकर रखते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ही टाइम मैनेजमेंट का न होना है। टाइम मैनेजमेंट आपको कई चीजें सिखाता है और आपके लिए कई चीजें आसान भी बना देता है। हमारे पास सीमित समय ही होता है, जिसमें से हमें यह पता होना चाहिए कि कौनसा काम प्रोडक्टिव है और कौनसा नहीं। आपको वो काम करना सबसे जरूरी है जिसको करने के बाद आपके अंदर कुछ प्रोडक्टिविटी आए। समय प्रबंधन करना भी एक व्यक्ति का कौशल हो सकता है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट के गुण में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपको फिर कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपका समय 'सीमित' है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है, आपके पास एक दिन में अपनी जरूरत की हर चीज को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। समय प्रबंधन को आम तौर पर गतिविधियों को व्यवस्थित करने, प्राथमिकता देने और योजना बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ काम पर आपकी परियोजनाएं ही नहीं हैं, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। जिस तरह से आप अपने घर का प्रबंधन करते हैं, उससे लेकर अपने व्यक्तिगत विकास और रचनात्मक शौक तक सब जगह टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा छात्रों के एक समूह पर किए गए 2014 के एक अध्ययन से पता चला है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इसे नियंत्रित करने से कथित तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है।

समय प्रबंधन प्रशिक्षण के दो और चार सप्ताह में, छात्रों ने तनाव की भावनाओं में कमी देखी थी। उचित समय प्रबंधन के साथ, व्यक्ति काम और आधुनिक जीवन की मांगों से परेशान होने की भावना को दूर कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि इसे कैसे कम किया जाए। काम, परिवार और पर्सनल लाइफ के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन आवश्यक है। यह आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए समय निकालने, थकान से बचने और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं और जिम्मेदारियों का सही अंदाजा नहीं होता। क्षमता और कौशल से अधिक काम हाथ में ले लेना आपको अव्यवस्थित कर सकता है, जिससे आप बेवजह तनाव में आ सकते हैं। इसलिए अपने डेली रूटीन और वर्क स्पीड का विश्लेषण कर यह तय करें कि आप कितने घंटे में कितना और कैसा काम कर सकते हैं।

राम शब्द सत्य, शौर्य, दया, तप और त्याग का वाचक हैं

सुरेंद्र अग्निहोत्री

विश्व महानायक राम का नाम युगो-युगो से जन के मन पर छाया हुआ है। राम का नाम चिरंजीवी रहेगा तथा अपनी गरिमा के समस्त वैभवों से विश्व मानस को संत अर्पण प्रदान करता रहेगा। सचमुच राम का नाम कल्पवृक्ष है। वाल्मीकि ने राम पर काव्य रचना की और आदिकवि की संज्ञा प्राप्त कर अमर हो गए। आचार्य रविषेण, आचार्य गुणभद्र, आचार्य विमलसूरि तथा स्वयंभू और पम्प ने एक से एक उत्तम भाव प्रवण पुराण एवं काव्य साहित्य में रामचरित लिखे हैं। संस्कृत के स्वतंत्र महाकवियों तथा मैथिलीशरण गुप्त ने राम पर काव्य रचना की है। एक हजार से अधिक दुनिया भर की विविध भाषाओं में राम की गाथा को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि काल की समस्त सत्ता को ललकार कर और विस्मृति के संपूर्ण उत्पादनों को निरस्कृत कर राम का यह अद्भुत चरित्र लोक मानस में प्रतिक्षण नवीन होकर चिरजीवी हो रहा है। श्रीराम का चरित्र वस्तुत: साकार और निराकार, निर्गुण एवं सगुण, अलख तथा लख, अव्यक्त एवं व्यक्त परमेश्वर 'ब्रह्म' का संशयरहित आभामय साकार प्रकटीकरण ही है। गोस्वामी तुलसीदास ने परमेश्वर के इन दोनों शाश्वत स्वरूपों का अत्यन्त स्पष्ट और पुष्ट रेखांकन प्रभु श्रीराम के अवतार वर्णन में किया है।

ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या कें गोद।।

सनातन धर्म में निर्गुण और सगुण तथा निराकार एवं साकार परमेश्वर के भ्रम का निराकरण मजबूत आध्यात्मिक तर्कशक्ति से किया गया है और यह निराकरण इस धर्म की विशाल वैचारिक पृष्ठभूमि एवं उदारता के साथ इसकी अद्भुत विलक्षण विशेषता भी कही जा सकती है। तत्वत: निराकार परमेश्वर ही भक्तों के प्रेमवश उसके कल्याण हेतु साकार रूप में प्रकट होते हैं।

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।।

निराकार 'ब्रह्म' भक्तों के प्रेमवश तो साकार स्वरूप में प्रकट होते ही हैं लेकिन वह परमेश्वर लोकरक्षा के लिए भी साकार रूप ग्रहण करते हैं एवं विविध अवतार के माध्यम से अपनी मनोरम लीला के साथ विभिन्न कालखण्ड में इस लोक में अवतरित होते रहते हैं। रामचरितमानस के बालकाण्ड में भगवान शिव माँ पार्वती से इस सत्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं।

जब जब होइ धरम कै हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी।। करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरनी।। तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा।।

भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन यही कहता है कि लोकमंगल एवं सज्जनों की रक्षा हेतु निराकार परमेश्वर साकार स्वरूप में अवतार लेकर जगत के कल्याण के साथ अपने लोक-चरित्र से धर्म और मर्यादा की पुनर्स्थापना करते हैं। भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन के अनुरूप ही प्रभु श्रीराम अपने अवतार की सार्थकता के प्रति संतों को आश्वस्त करते हैं।

एक अन्य कोण से देखा जाए तो राम एक बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तित्व है। उन्हें पिता, माता, पत्नी, भ्राताओं, गुरुजनों और मित्रों से भरपूर स्नेह व प्रेम मिला था। पिता उन्हें युवराज पद पर आसीन करना चाहते थे। माता कौशल्या का तो उन पर असीम स्नेह था ही। भ्राताओं पर राम का प्रगाढ़ स्नेह है तो भ्राताओं की उन पर परम भक्ति है। वचनबद्धता और आज्ञापालन राम के व्यक्तित्व के अन्य शाश्वत रेशे है।

कोरबा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़, भाजपा का नहीं खुला खाता

सरोज पांडे दिला पाएंगी जीत ?

देश के 543 और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र में से एक कोरबा लोकसभा क्षेत्र है. यह लोकसभा क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया है. इसके बाद 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की. कांग्रेस पार्टी के चरण दास महंत कोरबा लोकसभा सीट के पहले सांसद बने. इससे पहले कोरबा लोकसभा सीट जांजगीर लोकसभा सीट का हिस्सा था. यह वही जांचगीर लोकसभा सीट हैं जहां से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने साल 1984 में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और पहला चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें तब हार का सामना करना पड़ा था.

जांजगीर लोकसभा से पहले सांसद कांग्रेस पार्टी के अमर सिंह सहगल थे. 2009 में कोरवा लोकसभा बनने के बाद चरण दास महंत, फिर 2014 में बीजेपी डॉ बंशीलाल महतो फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी के ज्योत्सना चरण दास यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं.

ज्योत्सना महंत पहले सांसद

ज्योत्सना चरण दास महंत को 46.03 मत मिले थे. जबकि बीजेपी के ज्योति नंद दुबे को 43.72 प्रतिशत वोट मिले थे. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानि जीजीपी के उम्मीदवार जो तीसरे स्थान पर थे तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम 3.29 वोट मिले. तीसरे स्थान पर यहां नोटा और चौथे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के परमीत सिंह को 1.40 प्रतिशत वोट मिले थे.

2019 में 26349 वोटों से कांग्रेस की जीत

कांग्रेस नेता ज्योत्सना चरण दास महंत ने एक कड़े मुकाबले में बीजेपी के ज्योति नंद दुबे को 26,349 वोटों से हराया था. ज्योत्सना चरण दास महंत को जहां 523,410 वोट मिले वहीं बीजेपी के ज्योति नंद दुबे को 4,97,061 वोट मिले थे. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम37,417 तो वहीं पांचवे स्थान पर रहे बीएसपी के परमीत सिंह 15880 वोट मिले. बीएसपी उम्मीदवार को यहां नोटा 19,305 से भी कम वोट मिले थे.

2014 में बीजेपी के बंशीलाल की जीत

इससे पहले 2014 में बीजेपी के डॉ बंशीलाल महतो ने कांग्रेस के चरण दास महंत को एक नजदीकी मुकाबले में 4,265व वोटों से हराया था. बंशीलाल महतो को जहां 4,39,002 वोट मिले थे वहीं चरण दास महंत को 4,34,737 वोट मिले.यहां तीसरे स्थान पर रहे जीजीपी के हीरासिंह मरकाम को 52,753 वोट मिले. चौथे स्थान पर रहे आईएनडी के जीवन लाल रौतेल को 18,459 वोट मिले जबकि पाचवें स्थान पर यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमर नाथ पांडे थे उन्हें तब 14594 वोट मिले थे.

2009 में कांग्रेस पार्टी ने की पहली जीत

परिसीमन के बाद बने कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहली बार 2009 में चुनाव हुआ था. तब कांग्रेस पार्टी के चरण दास महंत ने बीजेपी के करुणा शुक्ला को 20737 वोटों से हराया था. कांग्रेस पार्टी के चरण दास महंत को जहां 3,14,616 वोट मिले थे वहीं करुणा शुक्ला को 2,93,879 वोट मिले जीजीपी के हीरा सिंह मरकाम यहां तीसरे स्थान पर रहे जबकि निर्दलीय शंभू प्रसाद शर्मा एडवोकेट 23,136 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे थे.

कोरबा लोकसभा वोट गणित

कोरबा लोकसभा में कुल आठ विधानसभा क्षेत्र आते हैं. जिनमें मरवाही, रामपुर, पाली-तानाखार, कटघोरा, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, भरतपुर-सोनहत और कोरबा शामिल है. इन विधानसभा क्षेत्रों में पांच विधानसभा क्षेत्र कोरबा जिले की जबकि तीन विधानसभा क्षेत्र अविभाजित कोरिया जिले की शामिल हैं. कोरबा जिले का गठन 25 मई 1998 को किया गया था. यह एक आदिवासी बहुसंख्यक जिला है. सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होने की वजह से कोरबा को छत्तीसगढ़ राज्य का पावर कैपिटलव भी कहा जाता है. यह जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से आदिवासी द्वारा संरक्षित जनजाति कोरवा (पहाड़ी कोरवा) का बसाया हुआ है.

कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 15,08,840 मतदाता है. इससे पुरुष मतदाता की संख्या 7,49,560 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,59,225 है. यहां थर्ड जेंडर निर्वाचक कुल 55 हैं. कोरबा में 2019 में हुए मतदान का कुल मतदान प्रतिशत 75.35% था. बीजेपी ने यहां सरोज पांडे को टिकट दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद को एकबार फिर से मैदान में उतारा है.

सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन

छत्तीसगढ़ का कोरबा राज्य के लिए सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है. यहां पर राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और एनटीपीसी के अलावा कई निजी कंपनियों के भी प्लांट हैं. इसके साथ ही यहां एशिया के सबसे बड़े खुले कोयला खदान गेवरा माइंस है. इसके साथ ही भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र भारत एल्युमिनियम कंपनी बालको भी यहीं है. कोरबा के सतरेंगा पहाड़ और झील को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

रेड जोन गुरुर ब्लॉक के 27 गांवों में होगी पानी की सप्लाई, दो साल में पूरी होगी योजना

बालोद। सामूहिक जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कनेरी जलप्रदाय योजना के तहत काम शुरू हो गया है। भू-जल स्तर में रेड जोन वाले गुरुर ब्लॉक में योजना अंतर्गत 27 गांवों में पानी की सप्लाई की जाएगी। वर्तमान में तांदुला जलाशय के पास इंटकवेल बनाने का काम शुरू हो गया है। योजना को पूरा होने में दो साल का समय का लग सकता है। तांदुला जलाशय से हो रहे रिसाव के पानी को 27 गांवों तक पहुंचाया जाएगा। योजना जिले की सबसे बड़ा जल प्रदाय योजना है। पीएचई पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 42 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च करेगा।

तांदुला जलाशय से 40 किमी दूर चिटौद तक बिछेगी मुख्य पाइप

तांदुला जलाशय के पास बालोद जलावर्धन योजना के तहत सम्पवेल बनाए गए है। पास ही दूसरा सम्पवेल बनाया जा रहा है। जलाशय से ग्राम चिटौद तक मुख्यपाइप लाइन बिछाई जाएगी। गांव व छोटी-बड़ी पाइपलाइन मिलाकर कुल 60 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी।

ग्राम धनोरा में फिल्टर प्लांट बनेगा

तांदुला जलाशय के पास बनाए जा रहे संपवेल से पानी खींचा जाएगा। पानी धनोरा जाएगा, जहां फिल्टर प्लांट बनेगा। फिल्टर प्लांट में पानी साफ होकर लगभग 40 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। योजना को 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

27 टंकी बनेगी

गुरुर विकासखंड के अंतर्गत कुल 27 गांवों में पानी की सप्लाई करेंगे। सभी 27 गांव में टंकी बनेगी और लगभग 8 हजार घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा।

इन गांवों में होगी पानी सप्लाई

गुरुर ब्लॉक के अकलवारा, तार्री, सरबदा, नर्बदा, दर्रा, धनोरा, मिरीटोला, चिटोद, आनंदपुर, उसरवारा, छेडिया, बगदई, अर्जुनी, चिरचारी, सोरर, धोबनपूरी, कोलिहामार, बोहाराडीह, कुलिया, कनेरी, कुम्हारखान, बोरतरा, कुम्हारखान, भरदा, भेजामैदानी व गुरुर नगर पंचायत भी पानी सप्लाई होगी।

गांवों में पाइपलाइन व नल कनेक्शन की जवाबदारी पंचायत की

पीएचई के मुताबिक मुख्य पाइपलाइन सड़क किनारे होते हुए चयनित गांव में पहुंचेगी। चयनित गांव में एक टंकी बनाएगी। लेकिन गांव में पाइपलाइन विस्तार व नल कनेक्शन की जवाबदारी पंचायत की रहेगी। पंचायत हर घर पीछे जलकर शुल्क लेकर कभी खराबी आए तो मेंटेनेंस कार्य भी कराएगी।

रिसाव होकर बह रहे पानी का होगा सदुपयोग

खास बात यह है कि तांदुला, खरखरा, गोंदली जलाशय मुख्य नहर के गेट से तांदुला का पानी रिसाव होकर व्यर्थ नहर में बहता है। शासन प्रशासन व विभाग ने इस पानी को उपयोग में लाने की योजना बनाई है। नहर के सामने गेट बंद किया जाएगा। रिसाव का पानी सीधे पाइपलाइन से सम्पवेल में जाएगा और सम्पवेल का कुआं भर जाएगा, जिसे सीधे पाइपलाइन से फिल्टर प्लांट भेजा जाएगा।

मासूमों के लिए खतरों से भरा है स्कूल का सफर

ऑटो और ई-रिक्शा वाले खचाखच भर कर पहुंचाते हैं स्कूल

बालोद। बालोद शहर में स्कूल वेन व बस होते हुए भी कई पालक ऑटो एवं ई-रिक्शा लगाकर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है। यह किसी खतरे से कम नहीं है। शिक्षा एवं परिवहन विभाग ने ऑटो एवं ई-रिक्शा में बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बीते दिनों में स्कूल वेन दुर्घटना की खबर आई थी। ई-रिक्शा व ऑटो से ज्यादा खतरा है। हालांकि कई परिजन स्कूल बस का किराया नहीं दे पाते हैं, इसलिए कम दाम पर ऑटो या ई-रिक्शा का उपयोग कराते हैं।

स्कूल बस का किराया नहीं दे पाते हैं कई परिजन

ऑटो एवं ई रिक्शा चालक लालच में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाते हैं। चालक की जरा सी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। ऑटो व ई-रिक्शा चालकों की बैठक लेकर उसे यातायात नियमों के बारे में बताने की जरूरत है।

ई रिक्शा व ऑटो की कोई जांच तक नहीं

जिले में दोपहिया वाहनों की जांच तेजी से की जा रही है। हर रोज चालान काटा जा रहा है, लेकिन ई-रिक्शा के मामले में अफसर आंखे बंद किए हुए हैं। अधिकांश ई-रिक्शा की कमान नाबालिगों के हाथों में है। रिक्शा पलटने की कई घटनाएं भी हो चुकी हैं।

रायगढ़ सीट पर साय परिवार का दबदबा

1999 से लगातार खिल रहा कमल

छत्तीसगढ़ की रायगढ़ लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है. यह सीट 1962 में पहली बार अस्तित्व में आई थी. यहां से मौजूदा सासंद भारतीय जनता पार्टी की गोमती साई हैं. वहीं, इस बार बीजेपी ने यहां से राधेश्याम राठिया को अपना प्रत्याशी बनाया है. रायगढ़ सीट पर 1999 से बीजेपी का कब्जा है.

1999 से 2014 तक विष्णुदेव साय लगातार सांसद रहे. इस समय विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर गोमती साई को उतारा था. गोमती साई ने 2019 में कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया को हराया था. रायगढ़ लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं. इन सीटों में जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया और धरमजयगढ़ हैं.

2019 लोकसभा चुनाव में क्या था रिजल्ट?

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गोमती साई ने कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया को 66,027 हजार वोटों से हराया था. गोमती को 658,335 लाख यानी 49 फीसदी वोट मिले जबकि लालजीत को 592,308 लाख यानी 44 फीसदी वोट मिले. वहीं, तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के इनोसेंट कुजूर रहे थे. कुजूर को 26,596 हजार वोट मिले थे.

2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे

2014 लोकसभा चुनाव में विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की आरती सिंह को 2,16,750 लाख वोटों से शिकस्त दी थी. विष्णुदेव साय को 662,478 तो वहीं आरती सिंह को 445,728 लाख वोट मिले थे. वहीं, तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी के कृपा शंकर भगत को 27,152 वोट मिले थे.

विष्णु देव साय लगातार 4 बार रहे सांसद

रायगढ़ लोकसभा सीट पर 1962 में राजा विजय भूषण सिंह देव पहली बार सांसद बने. 1967 में सारंगढ़ राजघराने की बड़ी पुत्री रजनी देव 1967 में सांसद बनीं. 1977 में कंवर समाज के आदिवासी नेता नरहरि प्रसाद साय जनता पार्टी से पहले सांसद बने. वहीं 1980, 1984,1991 में पुष्पा देवी सिंह कांग्रेस से सांसद चुनी गईं. 1999 से 2014 तक विष्णु देव साय लगातार सांसद रहे.

रायगढ़ का संक्षिप्त इतिहास

रायगढ़ का इतिहास काफी पुराना है. रायगढ़ को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है. इस शहर की अपनी सांस्कृतिक विरासत है. आजादी के पहले रायगढ़ में अंग्रेजो का प्रत्यक्ष राज न होकर राजाओं का शासन था. महाराज मदन सिंह जी को रायगढ़ राज्य का संस्थापक माना जाता है. चक्रधर सिंह महाराज स्वतंत्र रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे. महाराज चक्रधर सिंह के नाम पर यहां चक्रधर समारोह भी होता है, जहां देश-विदेश से कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार भाग लेते हैं. इस जिले की बहुसंख्यक आबादी गांवों में निवास करते हैं. रायगढ़ ढोकरा आर्ट के लिए फेमस है. यह आर्ट रायगढ़ के झारा आदिवासी समुदाय में काफी प्रचलित है.

जांजगीर-चाम्पा जिले के 12 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ रद्द

जांजगीर-चाम्पा। जिले के 12 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापामार कार्रवाई के दौरान इन सभी मेडिकल स्टोर में भारी अनियमितता के साथ निट्रोसन टैबलेट का अवैध कारोबार करते हुए पाया था.

सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अकलतरा बकाल के विश्वास मेडिकल स्टोर को 15 दिन, बम्हनीडीह ब्लॉक के समर्थन मेडिकोज, बलौदा ब्लॉक के दिशा मेडिकल स्टोर, नवागढ़ ब्लॉक के मेडिकल जोन को 10-10 दिनों और जैजैपुर ब्लॉक के आशीर्वाद मेडिकल स्टोर, पामगढ़ ब्लॉक के विवेक मेडिकल स्टोर, बम्हनीडीह ब्लॉक के चंद्र प्रकाश मेडिकल स्टोर को 5-5 दिनों और अकलतरा ब्लॉक के अरोरा मेडिकल स्टोर को 7 दिन, मयंक मेडिकल स्टोर, ? मेडिकल स्टोर नवागढ़, जमुना मेडिकोज अकलतरा और जानकी मेडिकल स्टोर जैजैपुर का लाइसेंस 3-3 दिनों के लिए निरस्त किया है.

इसके अलावा बम्हनीडीह ब्लॉक के धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर बम्हनीडीह का लाइसेंस 5 दिनों के लिए रद्द कर दिया है. बलौदा के निधि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर न्यायलयीन कार्रवाई की अनुमति के लिए उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया है.

जिला न्यायाधीश ने कहा, व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये कानून बनाया जाता है

महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

कोरबा। अनुभव भवन बालको नगर कोरबा में महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के प्रयोजनार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने अपने उद्बोधन में कहा गया कि बालकों एवं बालिकाओं का विवाह सही उम्र में करें, नाबालिक को गाड़ी चलाने न दें, अज्ञानता वश हमारे द्वारा बच्चों को दुपहिया वाहन चलाने के लिये दे दिया जाता है, दुर्भाग्यवश दुर्घटना होने पर पीड़ित पक्षकार को घायल एवं मृत्युकारित होने पर बहुत ही अधिक मुआवजा देना पड़ जाता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिये। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लायसेंस, वाहन का बीमा एवं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना आवयश्यक है। विधानसभा, संसद में व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित कैसा रखा जावें इस संबंध में सोच विचार कर कानून बनाया जाता है। कानून व्यवस्था को बनाये रखना बहुत ही मुश्किल का कार्य है, इसके लिये हमें कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कानून का पालन करना आवश्यक है। कानून व्यवस्था नहीं होने से आम नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पायेगें। कानून हर जगह लागू होता है, बच्चे के पैदा होने से उनके लिये जन्म प्रमाण पत्र तथा किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, कानून व्यक्ति को जन्म से मृत्यु उपरांत तक लागू होता है। हम अगर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा

अधिवक्ता संघ पामगढ़ के श्यामलाल सांडे अध्यक्ष और रोहिणी लाल बने सचिव

पामगढ़। अधिवक्ता संघ पामगढ़ के पदाधिकारियों का चुनाव अधिवक्ता कक्ष में हुआ। जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए मतदान हुआ जिसमें 108 अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए श्यामलाल सांडे को 62 मत एवं प्रेम कुमार खरे को 46 मत प्राप्त हुए और श्यामलाल विजयी हुए। सचिव पद के लिए रोहिणी लाल पटेल और कांति कुमार दिव्य के बीच मुकाबला हुआ। रोहणी लाल को 66 मत एवं कांति कुमार दिव्य को 42 मत प्राप्त हुए । रोहिणी लाल पटेल 24 मतों से जीत कर सचिव बने। अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष आशीष तिवारी, सह सचिव राजेश्वर लहरे, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार बंजारे, ग्रंथपाल सचिव करमु जांगड़े, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव सीताराम कुंभकार, कार्यकारिणी में अशोक कुमार टंडन, रामखिलावन कुर्रे,मनराखन लाल पंकज, अब्दुल कुरैशी, सरवन कुम्हार एवं संगीता जांगड़े निर्विरोध निर्वाचित हुए ।

31 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

जांजगीर-चांपा जिले में निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें 31 कर्मचारी अनुपस्थित रहें. इन सभी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

जानकारी के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के निर्देशन में लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों पर मतदान दल का प्रथम प्रशिक्षण 01 से 04 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है.

वहीं 3 अप्रैल को आयोजित मतदान दल के प्रशिक्षण में 31 अनुपस्थित कर्मचारी पाए गए. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय क्रमांक 01 जांजगीर में 14, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अकलतरा में 07 और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारागांव में 10 कर्मचारी पाए गए. कुल 31 संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए है.

कभी कांग्रेस का गढ़, अब लहरा रहा है भगवा

बीजेपी की टिकट पर भूपेश बघेल के भतीजे मैदान में

छत्तीसगढ़ का दूर्ग लोकसभा क्षेत्र देश के 543 और सूबे के 11 सीट में से एक है. यहां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है. इस सीट पर यह चुनाव हाई प्रोफाइल रहने वाला है. यहां कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू का मुकाबला विजय बघेल से मुकाबला होने वाला है. विजय बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे हैं. विजय बघेल ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर देखने के लिए मिली थी. हालाकि जीत भूपेश बघेल की ही हुई थी. लेकिन विजय बघेल पाटन में भूपेश बघेल को घेरने में कामयाब जरूर हो गए थे. विजय बघेल वर्तमान में यहां के सांसद हैं. कांग्रेस पार्टी ने यहां शुरुआती 6 चुनाव में जीत हासिल की थी.

2019 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी. विजय बघेल ने कांग्रेस प्रतिमा चंद्राकर को हराया था. विजय बघेल को जहां 61.1 प्रतिशत मत मिले थे वहीं प्रतिमा चंद्राकर को 32.86 प्रतिशत मत मिले थे. जबकि तीसरे स्थान पर रहे बसपा के गीतांजलि सिंह को 1.45 प्रतिशत मत मिले. चौथे स्थान पर रहे एसआरडीपी के हिदर भाटी को को यहां एक प्रतिशत वोट भी नहीं मिला.

2019 में 391978 वोटों से बीजेपी की जीत

2019 में यहां बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिमा चन्द्राकर को 391978 वोटों से हराया था. बीजेपी के विजय बघेल को 849,374 वोट मिले थे वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रतिमा चंद्राकर को 4,57,396 वोट मिले. जबकि बहुजन समाज पार्टी के गीतांजलि सिंह को महज 20,124 वोट मिले. इस चुनाव में चौथे स्थान पर रहे हिदर भाटी को 12,107 वोट मिले थे. हिदर भाटी एसआरडीपी की टिकट पर मैदान में थे. इससे पहले 2014 में कांग्रेस पार्टी के ताम्रध्वज साहू ने जीत दर्ज की थी. ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी के सरोज पांडे को 16848 वोटों से हराया था. ताम्रध्वज साहू को जहां 570,687 वोट मिले थे वहीं सरोज पांडे को 5,53,839 वोट मिले. जबकि तीसरे स्थान पर रहे आम आदमी पार्टी के विश्व रत्न सिन्हा को 17,455 वोट मिले थे. चौथे स्थान पर रहे निर्दलीय अरुण जोशी को 16529 पांचवे स्थान पर मुन्ना चंद्राकर को 15,600 वोट मिले.

दुर्ग का चुनावी इतिहास

दुर्ग में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के वासुदेव एस किरोलिकर ने जीत दर्ज की थी. 1957 और 1962 में हुए दूसरे और तीसरे चुनाव में मोहन लाल बकलियाल, 1967 में कांग्रेस के विश्वनाथ तामस्कर, 1968 में चंदूलाल चन्द्राकर, 1977 में जनता पार्टी के मोहन जैन,1980 और 1984 में कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर, 1989 में जनता दल के पुरूषोत्तम कौशिक, 1991 में चंदूलाल चंद्राकर. इसके बाद यहां भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद साहू ने लगातार चार बार 1996, 1998, 1999 और 2004 में जीत दर्ज की. 2009 में बीजेपी के ही सरोज पांडे जीत दर्ज की.

दुर्ग लोकसभा का वोट गणित

दुर्ग लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल नौ विधानसभा सीट हैं. इसमें सात सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है जबकि दो पर कांग्रेस पार्टी ने. दुर्ग के 9 विधानसभा सीट हैं-वैशाली नगर, बेमेतरा, अहिवारा, नवागढ़, पाटन, साजा, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण और भिलाई नगर. पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी के भूपेश बघेल ने जीत दर्ज की है. दुर्ग लोकसभा में कुल 19,40,269 मतदाता हैं. इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,61,685, महिला मतदाताओं की संख्या 9,78,518 जबकि थर्ड जेंडर निर्वाचक 66 हैं. 2019 में यहां कुल मतदान प्रतिशत 71.74त्न था. बात जातिगत वोट की करें तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र कुर्मी, यादव और साहू वोट बहुल है. यहां साहू वोटर 30-35 प्रतिशत, कुर्मी, 20-22 प्रतिशत, यादव 12-15 प्रतिशत और सतनामी वोटर 20-22 प्रतिशत हैं.

शिवनाथ नदी तट पर बसे दुर्ग में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कारखाना भिलाई इस्पात संयंत्र यहीं स्थापित है. दुर्ग को को लघु भारत भी कहा जाता है.स्वतंत्रता संग्राम में दुर्ग जिले के सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है.जैन समाज के तीन बड़े तीर्थ-नगपुरा और कैवल्यधाम दुर्ग जिले में हैं.दुर्ग में उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर का समृद्ध भंडार है. यहां का मैत्रीबाग चिड़ियाघर लोगों का पसंदीदा स्थल है.

एमएमआर चांपा और नवीन कालेज हसौद माडल कालेज के लिए चिन्हांकित

जांजगीर- चांपा। प्रदेश के सभी जिले में एक एक सरकारी कालेज को माडल कालेज बनाया जाएगा। यहां अधोसंरचना के साथ पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था होगी। साथ ही अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के तहत सभी जिले के एक एक सरकारी कालेज को माडल कालेज बनाया जाना है। इसके लिए कालेजों से प्रस्ताव भी मंगाया गया था। माडल कालेज के लिए जांजगीर चांपा जिले में शासकीय एमएमआर पीजी कालेज चांपा का चयन किया गया है। वहीं सक्ती जिले में शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद को माडल कालेज बनाया जाएगा।

इन कालेजों में उच्चस्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें अधोसरंचना के अलावा प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व अन्य स्टाफ की व्यवस्था होगी। ये कालेज के लिए रोल माडल होंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक शासकीय कालेज को माडल कालेज बनाया जाएगा। इसके लिए उच्चशिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी 36 जिलों के एक एक कालेज को माडल कालेज के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हांकित किया है। इसके लिए चयनित कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पर्याप्त अनुदान दिया जाएगा।

वहीं पीएम उषा के तहत भी अनुदान मिलेगा। इस कालेज का नैक मूल्यांकन में भी ग्रेडिंग बेहतर लाने प्रयास होगा। माडल कालेज लीड कालेज से हटकर होगा। लीड कालेज का कार्य जहां सभी कालेजों के बीच उच्चशिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के आदेशों का आदान प्रदान और चाही गई जानकारी को संकलित कर भेजना होता है। वहीं माडल कालेज अपनेआप में आदर्श होगा और इस कालेज का अन्य कालेज अनुकरण करेंगे।

बिना जीएसटी बिल के खप रहा सोना चांदी

जांजगीर- चांपा । जिले के कई सराफा दुकानों में बड़े पैमाने पर दो नंबर का सोना खपाया जा रहा है। इसका वैध दस्तावेज सराफा व्यवसायियों के पास नहीं है। सामान्य दिनों में बिना ई- वे बिल के सोने- चांदी को दूसरे प्रदेशों व बड़े शहरों से बेखौफ लाया जाता है। चुनाव के मद्दे नजर पुलिस की सख्ती से अवैध कारोबार पर अंकुश लगा है मगर चुनाव के बाद फिर से इस तरह के कारोबार होने लगेंगे। बिना जीएसटी बिल के सोना खरीदने वालों की तादात भी अधिक है इसलिए इस तरह का अवैध कारोबार फल फूल रहा है।

पहले सोने- चांदी का कारोबार विश्वास की कसौटी पर होता था मगर जीएसटी बिल की अनिवार्यता अब कानूनी पचड़े से बचने के लिए जरूरी हो गया हैमगर सस्ते में सोना - चांदी बेचनेकी होड़ में जिले के कई सराफा व्यवसायी सोना - चांदी खरीदने पर जीएसटी बिल नहीं देते। कई ग्राहक भी जीएसटी बिल नहीं लेना चाहते इसके पीछे वजह यह है कि काली कमाई का स्त्रोत उन्हें बताना पड़े गा इसलिए वे सराफा व्यवसायियों के पास से बिना जीएसटी बिल के सोना चांदी की खरीद्दारी करते हैं।

पेड व फेक न्यूज की निगरानी सतर्कतापूर्वक करने के निर्देश

जांजगीर- चांपा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव लिए गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में आज आयोजित किया गया। कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए मीडिया मानिटरिंग व सर्टिफिकेशन कार्य से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन सजगतापूर्वक करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट मीडिया की निगरानी पर ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत है।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाए। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए प्रिंट इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट मीडिया, रेडियो, एफएम, स्थानीय चैनल, आकाशवाणी का अनुवीक्षण करते रहें। अपर कलेक्टर एस पी वैद्य व एमसीएमसी नोडल अधिकारी आराध्या राहुल कुमार ने भी जानकारी प्रदान कर आवश्यक निर्देश दिए। मास्टर ट्रेनर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई, प्रिंट मीडिया इकाई, इंटरनेट मीडिया इकाई के अनुवीक्षण प्रमाणन के विविध बिन्दुओं का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने पेड न्यूज तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर सहायक संचालक जनसंपर्क एवं एमसीएमसी सचिव जरीफ खान, मास्टर ट्रेनर एम आर बंजारे, प्रिंट मीडिया इकाई देवेन्द्र कुमार यादव, दीपक कुमार यादव, अनुभव तिवारी,इंटरनेट मीडिया इकाई से हिमांशु डहरिया, ओम प्रकाश सिंह, बृजेश करियारे, विक्रांत साहू, इलेक्ट्रॉनिक इकाई से बसंत खुंटे, गोपेन्द्र पटेल, आदि उपस्थित थे।

बीजेपी का गढ़ रहा है रायपुर,

1991 के बाद नहीं जीत पाई कांग्रेस, क्या इस बार होगा उलटफेर ?

छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है. रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है. खारुन नदी के तट पर बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है. रायपुर लोकसभा सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी. यहां से मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी हैं. वहीं, इस बार भी बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है. उधर, कांग्रेस ने इस सीट पर विकास उपाध्याय को टिकट दिया है. करीब तीन दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है.

बता दें कि 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है. इसके बाद बाकी के कुछ साल को छोड़कर फिर यह बीजेपी की गढ़ माने जाने लगी. 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा. रमेश बैस लगाार जीतते रहे. बैस 1996 से 2014 तक लगातार सांसद रहे. 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार सोनी ने जीत दर्ज की. सुनील कुमार सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को हराया था. रायपुर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल आठ सीटें आती हैं. इन सीटों में बलौदा बाजार, भाटापारा, धरसीवा, रायपुर शहर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम, रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर शामिल हैं.

2019 में कौन जीता?

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुनील कुमार सोनी ने कांग्रेस के प्रमोद दुबे को 3,48,238 लाख वोटों से हराया था. सुनील कुमार सोनी को 837,902 लाख वोट जबकि प्रमोद दुबे को 489,664 लाख वोट मिले थे. वहीं, तीसरे नंबर पर बीएसपी के खिलेश कुमार साहू उर्फ खिलेश्वर रहे थे. खिलेश्वर को मात्र 10,597 हजार वोट मिले थे. इस साल यहां 68 फीसदी वोटिंग हुई थी.

2014 में क्या था रिजल्ट

2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश बैस ने कांग्रेस के सत्य नारायण शर्मा को शिकस्त दी थी. बैस ने शर्मा को 1,71,646 लाख वोटों से हराया था. बैस को 654,922 तो वहीं शर्मा को 483,276 लाख वोट मिले थे. वहीं तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के संदीप तिवारी रहे थे. संदीप को 15,139 हजार वोट मिले थे.

रायपुर लोकसभा सीट पर कितने मतदाता?

रायपुर लोकसभा सीट पर करीब 20,46,014 लाख मतदाता हैं. इनमें से 10,39,867 लाख पुरुष मतदाता हैं जबकि 10,05,871 महिला वोटर्स हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में 13,96,250 मतदाताओं ने मतदान किया था. मतलब यहां 68 फीसदी मतदान हुआ था.

कब-कब किसने जीता?

1952- भूपेन्द्र नाथ मिश्रा/मिनीमाता अगम दास गुरु- कांग्रेस
1957- बीरेंद्र बहादुर सिंह/केशर कुमारी देवी- कांग्रेस
1962- केशर कुमारी देवी -कांग्रेस
1967- लखन लाल गुप्ता -कांग्रेस
1971- विद्याचरण शुक्ल- कांग्रेस
1977- पुरुषोत्तम कौशिक-जनता पार्टी
1980- केयूर भूषण-कांग्रेस
1984- केयूर भूषण-कांग्रेस
1989- रमेश बैस- भाजपा
1991- विद्याचरण शुक्ल-कांग्रेस
1996- रमेश बैस- भाजपा
1998- रमेश बैस- भाजपा
1999 -रमेश बैस- भाजपा
2004 -रमेश बैस- भाजपा
2009 -रमेश बैस- भाजपा
2014 - रमेश बैस- भाजपा
2019 -सुनील कुमार सोनी- भाजपा

रायपुर का संक्षिप्त इतिहास

रायपुर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है. ऐसा माना जाता है कि रायपुर नगर की स्थापना 14वीं शत्ती ईस्वी में की गई थी. ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से रायपुर दक्षिणी कोशल का हिस्सा था और इसे मौर्य साम्राज्य के तहत माना जाता था. खारुन नदी के तट में बसा रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है. इसके साथ-साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है. रायपुर को व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों मे से एक माना जाता है. छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व रायपुर मध्य प्रदेश राज्य का अंग था. रायपुर खनिज संपदा से भरपूर है. यह देश में स्टील एवं लोहे के बड़े बाजारों मे से एक है. अग पर्यटन स्थलों की बात करें तो यहां बूढ़ा तालाब, माता कौशल्या मंदिर, भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर (दूधधारी मंदिर) है.

मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इससे हमारा और देश का भविष्य निर्धारित होता है-कमिश्नर

दुग। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत दुर्ग जिले के खालसा स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा मातृशक्ति द्वारा मतदाता जागरूकता पर आधारित रंगोली, मेंहदी, सलाद, व्यंजन तैयार कर प्रतियोगिता आयोजित की गई।

स्वीप के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाईजर द्वारा मतदाता जागरूकता तख्ती में लिखे स्लोगन के माध्यम से 07 मई को लोकतंत्र के महापर्व में शतप्रतिशत मतदान में सहभागिता के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल्याण कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बैंड के माध्यम से 'भारत हमे जान से प्यारा है' गीत की प्रस्तुति दी गई।

संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, निर्वाचन व्यय प्रेक्षक श्री प्रसन्ना वी. पत्तनसेठ्ठी एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाए गए रंगोली, पेंटिंग, मेंहदी, सलाद, रेडी-टू-ईट द्वारा तैयार व्यंजन का अवलोकन किया तथा सराहना की। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 'वोट जैसा कुछ नही वोट जरूर डालेंगे हम' सेल्फी बूथ में सेल्फी भी खिंचाई। संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने मतदान के लिए जाना है, के नारे के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोटिंग कर अपना योगदान दे। मतदान करना अधिकार ही नही बल्कि कर्तव्य भी है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, इससे हमारा और देश का भविष्य निर्धारित होता है। मतदान सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, मतदाता इसकी ताकत को पहचानें और चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करें। युवाओं एवं मातृशक्ति ने एक स्वर में इस लोकतंत्र के महापर्व पर शत-प्रतिशत मतदान करने की सहमति दी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिले से शतप्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप टीम द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने युवाओं को बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने हेतु सहयोग करने के लिए स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी मातृशक्ति आज यह प्रण लेकर जाएं कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अन्य लोगों का भी चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। आधा घंटा 7 मई को हम देश के प्रति निकाले।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अश्वनी देवांगन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ता, सुपरवाईजर को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में 51 प्रतिशत मतदान केन्द्रों का संचालन मातृशक्ति करेगी।

दुर्ग में शुद्ध पानी प्रदान करने जिला प्रशासन को गेल सीएसआर मद से मिले 25 लाख रूपए

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी से गेल (इंडिया) के महाप्रबंधक नजीब कुरैशी ने मुलाकात की। गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी है और एशिया में शीर्ष गैस उत्पादकों में से एक है। यह एक महारत्न कंपनी है जो व्यवसायिक गतिविधियां जैसे गैस प्रोसेसिंग एवं तरलीकृत पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन और विपणन का कार्य करती है।

देश के कई राज्यों के आर्थिक विकास में गेल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके तहत राज्य के प्रमुख जिलों एवं शहरों को ट्रंक लाइन से जोड़ा जा रहा है जिससे औद्योगिक वाहनों और घरेलू खपत के लिए प्राकृतिक गैस की पहुंच को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

इसी कड़ी में दुर्ग जिले में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से गेल (नागपुर-रायपुर-झाड़सूगुडा) पाइपलाइन के अन्तर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के तहत 21 ग्रामों के स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में परियोजना संचालित की जा रही है।

जिसके लिए गेल (इंडिया) के महाप्रबंधक नजीब कुरैशी ने 50 लाख की परियोजना में पहली किस्त स्वरूप 25 लाख रूपए की राशि कलेक्टर सुश्री चौधरी को प्रदान की। इस दौरान श्री बाला चंद्रा उप महाप्रबंधक गेल (इंडिया) लिमिटेड एवं श्री सौरभ सिंह मुख्य प्रबंधक गेल (इंडिया) लिमिटेड मौजूद थे।

धूल खा रहे बेरोजगारों के 33 हजार आवेदन

राजस्व विभाग में 107 पदों पर होनी थी सीधी भर्ती

बलौदाबाजार। राजस्व विभाग में जिला स्थापना एवं भू अभिलेख शाखा अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ के 106 पदों पर सीधी भर्ती हेतु कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार द्वारा 2023 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से 21 जून तक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया था।जिसके बाद जिले के अलावा राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों से निर्धारित तिथि तक इन पदों हेतु करीब 33 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन इस संबंध में आगामी प्रक्रिया लंबित होने की वजह से वर्तमान में युवाओं से प्राप्त आवेदन पत्र बोरी में बंद कचरे की भांति कलेक्ट्रेट के एक कक्ष में करीब साल भर से पड़े हुए धूल खा रहे हैं।

जबकि इसी दौरान महासमुंद व बालोद जिले जिलों में इन पदों हेतु आमंत्रित आवेदन के पश्चात अन्य प्रक्रिया पूर्ण कर सीधी भर्ती का कार्य संपन्न भी हो चुका है। वहीं अब तक बलौदाबाजार जिले में भर्ती प्रक्रिया लंबी रहने से सैकड़ो युवक युवतियों के मध्य निराशा व्याप्त है। उनका इंतजार अब चुनाव आचार संहिता संपन्न होने तक और बढ़ाया गया है।

विदित हो कि जिल कलक्टरेट जिला स्थापना हेतु भू अभिलेख शाखा द्वारा 30 मई 2023 को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु राजस्व विभाग वित्त स्थापना अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 के 26 पदों स्टेनो टाइपिस्ट के 14 पदों वाहन चालक के 13 पदों भत्य के 21 पदों पर अर्दली के 3 पदों चौकीदार की 9 पदों फराश के 6 पदों प्रोफेसर सरवर के 14 पदों समेत 106 तथा भू अभिलेख शाखा अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 के 1 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था।

संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार में विभिन्न विभाग अंतर्गत इस श्रेणी के कर्मचारियों की अत्यधिक कमी की वजह से इस बात की उम्मीद जागृत हुई थी कि शीध्र इस भर्ती के माध्यम से उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकेगा। आवेदन जारी होने के बाद इन सभी पदों के विरुद्ध आवेदन जमा करने की होड़ सी मच गई और कल 107 पदों के विपरीत लगभग 33 हजार से अधिक आवेदन जिले में प्राप्त हुए।

अब बेरोजगार कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे

इसी दौरान तत्कालीन कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण तथा प्रशासन के चुनाव मोड में आ जाने तथा अन्य कारणों से यह प्रक्रिया लंबित पड़ी रही। अब जिला के सैकड़ो बेरोजगार अभ्यर्थियों इस संबंध में जानकारी हेतु कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं।जबकि उन्हें कोई संतुष्टि प्रद जवाब भी प्राप्त नहीं हो रहा है। आवेदकों के अनुसार इसी दौरान महासमुंद और बालोद जिले में इन पदों पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बलौदाबाजार जैसे साधन संपन्न जिले में लंबित रहना बेरोजगारों युवाओं के साथ अन्याय करने जैसी है। उन्होंने आचार संहिता के पश्चात तत्काल ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग जिला प्रशासन समेत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन टंक राम वर्मा से की है।

भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी नहीं -एसडीएम

इस संबंध में एसडीएम दीप्ति गोते से चर्चा किए जाने पर उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों पूर्व बलौदाबाजार जिला में पदस्थ हुई है। अतः भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर ही इस संबंध में कुछ बता पायेगी।

वहीं जब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि यह बात आपके द्वारा संज्ञान में लाई है। चुनाव आचार संहिता संपन्न होने के पश्चात अधिकारियों से चर्चा कर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएंगे।

बलौदाबाजार-लवन मार्ग भूसा भरे वाहनों से दुर्घटना का खतरा

बलौदाबाजार। इन दिनों बलौदाबाजार गिधौरी राष्ट्रीय राजमार्ग 130 बी से गुजर रहे ओवरलोड वाहनों, क्षमता से अधिक भूंसे से भरे वाहनों से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ रहता है। इसके बावजूद भूंसे भरे हुए ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने से वाहन चालकों का हौसला बुलंद हो जाता है, और बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

गौरतलब हो कि ट्रक में 15 से 20 फीट ऊपर तक भरकर दिनदहाड़े परिवहन किया जा रहा है। जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। जबकि मुख्य मार्ग पर पुलिस थाना भी स्थित है। लगता है उन्हें किसी हादसे का इंतजार है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस प्रकार से दौड़ रही भूंसे से भरा ट्रकों की वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। वही, ट्रक के अलावा मेटाडोर, पिकअप, ट्रैक्टर सहित अन्य प्रकार के वाहनों पर भूंसा भरकर उसको बेचने के लिए पड़ोसी राज्यों में लेकर जा रहे हैं। जिसके चलते रोजाना इन सडको पर भूसे से भरा वाहन परिवहन हो रहा है।

भूंसे से भरे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। भूंसा भरकर वाहन चालकों के द्वारा खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बाद भी जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे है। इस प्रकार के वाहनों का रोड पर चलने से पीछे चल रहा वाहन को आगे का हिस्सा समझ नहीं आता है, इस वजह से भी हादसे होते है। बेखौफ चल रहे इस प्रकार के वाहनों पर जिम्मेदारों को ध्यान देने की जरूरत है।

समय-सीमा में करें सभी कार्यों का निपटारा-कलेक्टर

बलौदाबाजार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के. एल.चौहान ने संयुक्त जिला कार्यालय में आयोजित समय- सीमा की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखकर कार्यों का निपटारा समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में पेयजल,शौचालय, व्हील चेयर,वेबकास्टिंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को मतदान दिवस के 7 दिवस पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश संबधित अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर चौहान ने प्रत्येक विधानसभा में 10-10 आदर्श मतदान केंद्र, 205 संगवारी मतदान केंद्र,4 युवा मतदान केंद्र तथा 4 दिव्यांग मतदान केंद्र में आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने मतदान दलों के लिए बस एवं अन्य वाहन अधिग्रहण के लिए रूट का निर्धारण करते हुए आवश्यता अनुसार वाहन अधिग्रहण करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिए। इसके साथ ही मतदान के दिन सभी राजव अनुभागों में 2-2 वाहन आरक्षित करने कहा ताकि जरूरत पडने पर शीघ्र वाहन उपलब्ध हो सके। उन्होंने 85 वर्ष से अधिक एवं दिव्यांग मतदाताओ के लिए होम वोटिंग के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने कहा। कलेक्टर ने मतदान दलों का प्रशिक्षण, ईव्हीएम का कमीशनिंग, स्ट्रोंग रूम में आवश्यक व्यवस्था, मतदान सामग्री वितरण एवं संग्रहण, मतदान सामग्री वितरण स्थल पर मतदान दलों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पर विस्तार से समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए।

सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी समेत चार अब भी फरार

शिरीष पांडे महान मिश्रा दुर्गा टंडन मोंटी मरैया

बलौदाबाजार। नगर में अब तक सर्वाधिक चर्चित सेक्स रैकेट के मामले में मुख्य आरोपी समेत चार अन्य को गिरफ्तार कर पाने में पुलिस द्वारा गठित पांच टीम अब तक सफल नहीं हो पाई है।

ज्ञात हो कि 15 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक गुमनाम पत्र के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा करते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। जिसके बाद राजस्व मंत्री के कड़े निर्देश पर 30-31 मार्च को मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त गुमनाम पत्र में इस पूरे गिरोह में शामिल जिन लोगों के नाम उल्लेख किया गया था, उसमें से आरोपी दुर्गा टंडन, प्रत्यूष मरैईया के अलावा अन्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि पत्र में उल्लेखित नाम में शामिल गिरोह का सरगना शिरीष पांडे, पत्रकार आशीष शुक्ला, पुष्पमाला फेकर व एक अन्य के खिलाफ भी मामले में प्राथमिकी दर्ज विवेचन किया जा रहा है।

इस संबंध में अन्य कुछ लोगों ने पूछताछ में भी हो चुकी है, परंतु पत्र में स्पष्ट तौर पर थाना सिटी कोतवाली में पदस्थ दो पुलिस कर्मियों के नाम उल्लेख होने के बावजूद अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य आरोपी शिरीष पांडे की गिरफ्तारी एवं उससे पूछताछ में पुलिस कर्मियों के नाम उल्लेख करने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं।बताया जाता है कि शिरीष पांडे और पुष्पमाला फेकर की गिरफ्तारी के साथ ही मामले में लिप्त नगर के कुछ नेताओं व पुलिस कर्मियों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

ज्ञात हो कि करीब पखवाड़े भर पूर्व पुलिस द्वारा सैक्स रैकेट में शिरीष पांडे व पुष्पमाला फेकर को गिरोह का प्रमुख सरगना बताया गया था। पश्चात मामले में संलग्न आरोपी नेता अधिवक्ता व पत्रकार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया था।

इस दौरान पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु पांच टीमों का गठन करने की जानकारी दिया गया था परंतु अब तक यह टीम मुख्य आरोपी के ठिकाने की तलाश तक नहीं कर पाई है।

फूड पाइजनिंग से ग्रस्त मरीज हुए स्वस्थ

सारंगढ़ बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ क्षेत्र के ग्राम रानीगढ़ छुइहा के दशगात्र कार्यक्रम में भोज किए नागरिक विषाक्त भोजन (फूड पाइजनिंग) से बीमार हो गए। कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. अवधेश पाणिग्राही ने बिलाईगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाकर मरीजों का हाल-चाल जाना, जिसमें से कई स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। श्री पाणिग्राही ने बीएमओ श्री पुष्पेन्द्र वैष्णव से मरीजों के द्वारा दिए जा रहे उपचार के संबंध में जानकारी ली और सतत् उपचार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की आवश्यकता और इलाज के बारे में अवगत कराने के लिए कहा। स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से रानीगढ़ छुइहा में स्वास्थ्य विभाग का कैम्प लगाया गया, जिसमें मरीज मिलने की स्थिति में उसका तात्कालिक इलाज किया जा सके।

सारंगढ़ बिलाईगढ़-एमसीएमसी टीम का प्रशिक्षण संपन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिले में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के दलों को कलेक्टोरेट में प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी एमसीएमसी देवराम यादव के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट, रेडियो और सोशल मीडिया टीम को पैड न्यूज, फेक न्यूज, अभ्यर्थियों द्वारा मीडिया सर्टिफिकेशन एवं अनुप्रमाणन के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान एमसीएमसी टीम कार्य किए ममता साहू, पूनम महिलाने, संजीता मिंज, अंजूलता कुजूर और देवानंद सोनी, शिवशंकर साहू पुन: लोकसभा एमसीएमसी टीम में कार्य कर रहे हैं।

एसडीएम वासु जैन ने खेत में जाकर फसल क्षति का आंकलन किया

सारंगढ़ बिलाईगढ़। आईएएस श्री वासु जैन एसडीएम सारंगढ़ के द्वारा बेमौसम बारिश से फसलों के क्षति का आंकलन करने सरिया क्षेत्र के ग्राम पुरैना का दौरा किया गया। श्री जैन ने कई किसानों के खेतों में जाकर सरसों और गेहूं के फसलों का अवलोकन किया, जिसमें फसल खड़ी पाई गई। वर्तमान स्थिति में 20 प्रतिशत फसल क्षति आंकी गई है। पटवारी के द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट आने पर किसानों के फसल क्षति का मुआवजा का निर्धारण किया जाएगा। राजस्व पुस्तक परिपत्र अनुसार 33 प्रतिशत फसल क्षति होने पर मुआवजा देने का प्रावधान तहसीलदार सरिया श्री शनि पैकरा के द्वारा बताया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, पटवारी, किसान आदि उपस्थित थे।

4 महीने में नांदगांव मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा

राजनांदगांव। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के अलग-अलग विभाग में पदस्थ चिकित्सक नौकरी छोड़कर निजी अस्पतालों अथवा अन्य शहरों का रूख कर रहे हैं। पिछले 4 महीने के भीतर 9 चिकित्सकों ने नौकरी छोड़ दी है। वहीं प्रशासकीय तबादले से भी कॉलेज के कई विशेषज्ञ चिकित्सक बाहर पदस्थ हो गए हैं। जिसके चलते कई महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद रिक्त हो गए हैं। खासतौर पर रेडियोलॉजिस्ट एक्स-रे समेत हड्डी, कैंसर व नेत्र जैसे महत्वपूर्ण विभाग के चिकित्सकों के बगैर मेडिकल कॉलेज चल रहा है। चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को जांच में दिक्कतें आ रही है। मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से चिकित्सकों ने निजी कारणों का हवाला देकर दूसरे शहर में जाने में रूचि ली है। इससे मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है।

बताया जा रहा है कि हाल ही में रेडियोलॉजिस्ट और एक्स-रे विभाग से तीन चिकित्सकों का रायपुर तबादला हो गया। यह तबादला शासन स्तर पर हुआ है, लेकिन अन्य चिकित्सक कम वेतन और मेडिकल कॉलेज में व्याप्त कुप्रबंधन से हताश होकर इस्तीफा दिया है।

चार माह में एकमात्र नेत्र सर्जन डॉ. सौम्या डुलानी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश डुलानी, सर्जन विभाग के एचओडी रूपनारायण साहू, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. चैतन्य साहू और प्रसूति विभाग की एक महिला चिकित्सक व मेडिसीन विभाग के डॉ. किशोर ने इस्तीफा दिया है।

इस तरह चार माह के भीतर 9 से ज्यादा चिकित्सकों ने नौकरी छोड़ दी है। जूनियर डॉक्टरों के जरिये वैकल्पिक व्यवस्था पर प्रबंधन का जोर था, लेकिन कई जूनियर डॉक्टरों ने भी पीजी की पढ़ाई के लिए नौकरी छोड़ दी है। आने वाले दिनों में व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। वजह यह है कि चिकित्सकों की कमी से मेडिकल कॉलेज में उच्च स्तरीय इलाज की संभावना क्षीण हो गई है। आचार संहिता के कारण नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है।

राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी आबादी का इलाज होता है। न सिर्फ राजनांदगांव, बल्कि बालोद, कवर्धा एवं आसपास के पड़ोसी राज्यों के मरीज भी उपचारार्थ दाखिल होते हैं। फिलहाल चिकित्सकों के इस्तीफे से निपटने के लिए प्रबंधन के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ना तय है।

अनुशासनहीनता पर दो पुलिसकर्मी लाईन अटैच

केसीजी एसपी ने की कार्रवाई

राजनांदगांव। कदाचरण एवं अनुशासनहीनता पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने दो पुलिस कर्मियों को लाईन हाजिर कर दिया। एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को हिदायत दी कि संवेदनशील रहकर कार्य करें। जिससे आमजन का विश्वास बढ़े।

मिली जानकारी के अनुसार केसीजी जिले के एसपी त्रिलोक बंसल ने आपराधिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने अनुशासन बनाए रखने विभागीय सख्ती भी शुरू कर दी है। एसपी ने दो पुलिस कर्मियो के खिलाफ कार्रवाई करते लाईन अटैच कर दिया है। एसपी ने कहा कि वे शिकायत और अनुशासनहीनता पर किसी भी पुलिसकर्मी को बक्शा नहीं जाएगा। साथ ही अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने हेतु ईनाम भी दिया जाएगा, जो पुलिसकर्मी आम जनता की निस्वार्थ सेवा करेंगे, उन्हे समय-समय पर प्रशंसा पत्र एवं ईनाम दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार एसपी श्री बंसल को खैरागढ़ थाना के सहायक उप निरीक्षक शंकर कारूणिक एवं प्रधान आरक्षक सियाराम ध्रुर्वे द्वारा आम जनता से लगातार कदाचरण करने की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते दोनों को रक्षित केन्द्र खैरागढ़ लाइन हाजिर करने तत्काल आदेशित कर दिया है।

एसपी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस का कार्य आमजन की तकलीफों को दूर करना, जनता से अच्छा व्यवहार एवं अपराधियों के प्रति सख्ती कर आम जन के लिए भयमुक्त, अपराध मुक्त समाज बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे पुलिसकर्मी जो निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं कदाचरण में लिप्त अनुशासनहीन आचरण करने वाले पुलिस कर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर-एसपी ने किया नक्सल प्रभावित इलाकों का भ्रमण

राजनांदगांव। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। दोनों अधिकारी मोटर साइकिल से पेट्रोलिंग करते थाना गातापार, कैम्प भावे, मलैदा थाना बकरकट्टा क्षेत्र का भ्रमण कर कैम्प व थाना में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हालचाल और आगामी लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष ड्यूटी करने की हिदायत दी।

मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 अप्रैल को कलेक्टर श्री वर्मा और एसपी श्री बंसल ने आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते नक्सल प्रभवित क्षेत्रों में मोटर

साइकिल से भ्रमण करते थाना गातापार, बकरकट्टा, मलैदा, भावे कैम्प का भ्रमण किया, जहां थाना में उपस्थित जिला बल एवं डीआरजी बल से आदर्श आचार सहिता का पालन करने का निर्देश दिया गया। थाना साल्हेवारा एवं बकरकट्टा क्षेत्र के अति नक्सल संवेदनसील जगहों पर भ्रमण के दौरान चुनाव हेतु आने वाले अर्द्धसैनिक बलों के रूकने के स्थानों, कॉलेज, स्कूल का निरीक्षण कर जायजा लिया। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नक्सल ऑपरेशन अजीत ओगरे एवं थाना प्रभारी बकरकट्टा राजेश देवदास, गातापार प्रभारी उप निरी. देवाराम भास्कर को आगामी लोकसभा चुनाव एवं मतदान केन्द्र के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा दुरूस्त कराने निर्देश

पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा दुरूस्त कराने निर्देश

राजनांदगांव। चैत्र नवरात्र पर्व 2024 में वाहनों के पार्किंग व्यवस्था कराने वालों व पार्किंग संचालकों का पुलिस ने थाना परिसर में बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

मिली जानकारी के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर्व में मां बम्लेश्वरी देवी के दर्शन हेतु डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते 11 अप्रैल को थाना परिसर डोंगरगढ़ में एसडीओपी आशीष कुंजाम, तहसीलदार मुकेश ठाकुर,नगर पालिका सीएमओ चन्द्रकान्त शर्मा, नायब तहसीलदार विजय साहू एवं थाना प्रभारी डोंगरगढ़ सीआर चन्द्रा द्वारा मेला में पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने वाले संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में नगर पालिक परिषद अध्यक्ष डोंगरगढ़ सुदेश मेश्राम भी शामिल हुए।

मीटिंग में पार्किंग व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रकार के आवश्यक चर्चा कर पार्किंग संचालकों से सुझाव प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश देकर पार्किंग व्यवस्था हेतु राशि दोपहिया वाहन 10 रुपए, चारपहिया वाहन 100 रुपए एवं बस व अन्य वाहन के लिए 150 रुपए का पार्किंग शुल्क राशि तय कर पार्किंग स्थल में रेट लिस्ट बोर्ड लगाने, रसीद देने, पार्किंग स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पार्किंग स्थल पर संचालक का नाम नंबर लेख करने, किसी भी दर्शनार्थी से पार्किंग के नाम पर निर्धारित राशि से ज्यादा अवैध वसूली नहीं करने संबंधी समझाईस दिया गया है।

2 लाख का शराब और वाहन जब्त, 2 बंदी

राजनांदगांव। अंतरराज्यीय शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने 39 पेटी अंग्रेजी शराब एवं 90 लीटर महुआ लहान कुल कीमती दो लाख 8 हजार 260 रुपए एवं टाटा सफारी वाहन कीमती 8 लाख रुपए को जब्त किया।

पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल को ग्राम लेड़ीजोब में मुकेश जंघेल के घर में अवैध शराब डंप होने व शराब लाने के लिएउपयोग किए वाहन घर के सामने खड़ी होने की सूचना पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ सीआर चंद्रा द्वारा अपनी टीम एवं सायबर सेल राजनांदगांव प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा व अन्य स्टॉप के साथ ग्राम लेडीजोब आरोपी के घर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी मुकेश जंघेल एवं महेन्द्र वर्मा मोहारा थाना डोंगरगढ़ को पकडक़र आरोपी मुकेश जंघेल के घर

से एवं टाटा सफारी वाहन से कुल 39 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब मध्यप्रदेश में निर्मित छत्तीसगढ़ सरकार को बिना टैक्स चुकाए शराब एवं 90 लीटर महुआ लहान कीमती 2 लाख 8 हजार 260 रुपए एवं टाटा सफारी वाहन कीमती 8 लाख रुपए को जब्त किया।

आरोपियों के विरूद्ध धारा-34(2) 36 आबकारी एक्ट कायम कर गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी राजू साहू बुधवारी पारा डोंगरगढ़ घटनास्थल से फरार है।

शराब दुकान से दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर 20 लाख रुपये की लूट, बदमाशों की तलाश जारी

बलौदाबाजार, कसडोल। कटंगी में शराब दुकान में लूट का मामला सामने आया है। जहां दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाश कलेक्शन के लाखों रुपये लूटकर फरार हो गए। अब पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार कटंगी शराब दुकान में मंगलवार को दिनदहाड़े दो बदमाश बंदूक की नोक पर 20 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, साथ ही शराब दुकान के चार कर्मचारियों को थाने ले जाकर पूछताछ की गई है। बताया गया कि पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। साथ ही फरार आरोपितो को पकड़ने के लिए जिले के सभी थाना और चौकियों में नाकाबंदी की गई है।

कसडोल थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि नकाबपोश बदमाश शराब भट्टी के अंदर से पैसा लूटकर फरार हुए हैं। लूट को अंजाम देने वाले लोग देहात की ओर भागे हैं।

डीएवी स्कूल फीस को लेकर विवाद, अफसरों ने ली बैठक

दल्लीराजहरा। जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर के निर्देश पर सभी ब्लाक शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है।

इस बैठक में डीएवी, बीएसपी प्रबंधन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ हुई बैठक की विषय वस्तु रखी गई। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के मुश्ताक अहमद ने कहा कि सभी निजी स्कूलों का ऑडिट प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिससे पता चले कि स्कूल जो कि मान्यता लेने के समय शपथपत्र देते हैं कि नो प्रॉफिट नो लास में स्कूल का संचालन करेंगे मगर मान्यता मिलते ही शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया जा रहा है।

कापी पुस्तक मोजा टाई सभी चीजें स्कूल स्वयं बेच रहा है और पालकों पर दबाव बनाया जाता है खरीदने के लिए जोकि कहीं से भी सही नहीं है और कलेक्टर को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

ज्ञात हो कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा सीएसआर मद से गैर बीएसपी बच्चों की फीस के लिए

लिए दो सत्रों से सत्र 2022-23 में 2 करोड़ 18 लाख एवं सत्र 2023-24 में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान डीएवी स्कूल प्रबंधन को कर चुकी हैं, और जिसकी लिखित जानकारी सूचना के अधिकार में बीएसपी के अधिकारियों द्वारा स्वयं दिया भी गया है, मगर उसके बाद भी उस पैसों का लाभ क्षेत्र की गरीब आदिवासियों के बच्चों को अभी तक नहीं मिला है, जो कि जांच का विषय है।

बैठक में मुख्य रूप से भारतीय मजदूर संघ की ओर से मुश्ताक अहमद, एमपी सिंग, लखनलाल चौधरी, डौंडी बीआरसी एस एन शर्मा, डीएवी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य और एसडीएम राजहरा आर के सोनकर उपस्थित थे।

10वीं-12वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान, रसायन, अंग्रेजी और संस्कृत में मिलेगा बोनस अंक

धमतरी। बोर्ड परीक्षा के दौरान इस साल छात्र-छात्राओं को त्रुटिपूर्ण प्रश्नों ने काफी उलझाया। दसवीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं के पर्चे में आंशिक त्रुटि सामने आई है। छात्रों की शिकायत पर माध्यमिक शिक्षा मंडल अब छात्रों के हित में ऐसे प्रश्न पत्र में बोनस अंक देने का आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि धमतरी जिले में बोर्ड परीक्षा में कुल 18 हजार 565 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। इसमें कक्षा दसवीं में 10 हजार 509 तथा बारहवीं में 8 हजार 56 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दिलाई। बीते साल की अपेक्षा इस बार दोनों ही कक्षाओं के प्रश्न पत्र काफी कठिन आए थे।

इसके अलावा 10वीं के विज्ञान और 12वीं के रसायन, अंग्रेजी और संस्कृत में पर्चे में आंशिक त्रुटि रही। इसे हल करने में छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। त्रुटि के चलते अधिकांश छात्रों ने संबंधित प्रश्न हल नहीं कर पाए। इसे लेकर छात्र-छात्राओं ने यह पर्चा फिर से कराने अथवा बोनस देने की मांग

की थी। आमदी सेजेस के छात्र-छात्राओं ने बाकायदा कलेक्ट्रेट और डीईओ दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। अंततः माध्यमिक शिक्षा मंडल को बोनस अंक देने का आदेश जारी करना पड़ा। यह आदेश धमतरी शिक्षा विभाग में पहुंच गया है।

बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं और बारहवीं बोर्ड कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। धमतरी में इसके लिए शिवसिंह वर्मा उच्चतर माध्यमिक शाला को मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया हैं, जहां मूल्यांकन के लिए 2 सौ से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दसवीं के विज्ञान में त्रुटि के चलते 2 अंक और बारहवीं के अंग्रेजी, रसायन और संस्कृत में 1-1 अंक बोनस दिया जाएगा। यह अंक नतीजे घोषित होने के पहले ही परीक्षार्थियों की अंकसूची में जोड़ दिए जाएंगे।

डीईओ तेजराम जगदल्ले ने कहा कि दसवीं और बारहवीं के कुछ विषयों के सवालों में त्रुटियां पाई गई। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोनस देने के लिए आदेश जारी कर दिया है।

संगीत विवि में नियम विरुद्ध कुलपति की नियुक्ति- यादव

खैरागढ़। इंदिरा कला संगीत विवि की वर्तमान कुलपति पद्श्री मोक्षदा (ममता) चंद्राकर की नियुक्ति नियम विरुद्ध की गई है। श्री यादव द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए सेनि शिक्षक बीआर यादव ने कुलपति की नियुक्ति को नियम का उल्लंघन बताया है।

छुईखदान टिकरीपारा निवासी बीआर यादव ने कहा कि संगीत विवि में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन के पात्रता संबंधी नियमों को भी दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार कुलपति की नियुक्ति के लिए विनिमय 2018 का पालन सभी विवि के लिए अनिवार्य है। राजभवन द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार नियुक्ति के लिए दस सालो का प्रोफेसर के पद पर कार्य करने व अकादमिक अनुभव होना जरूरी है वहीं यूजीसी के विनिमय 2018 और विवि के अध्यादेश क्रमांक 171 अनुसार चयन को लेकर गठित समिति से अनुशंसित नामों में से ही कुलपति नामित किया जाता है।

बीआर यादव ने कहा कि मोक्षदा चंद्राकर की नियुक्ति में इन सभी नियमों व निर्देशों की अनदेखी की गई। ममता चंद्राकर ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नियमित नौकरी नहीं किया है। पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से प्राप्त पुरस्कार या सम्मान को प्रोफेसरशिप के समकक्ष नहीं माना गया है। संविधान के आर्टिकल 254 अनुसार राजकीय नियम और केंद्रीय नियमों के बीच विरोधाभास की स्थिति निर्मित होने पर केंद्रीय नियमों को सर्वोपरि माना गया है और यूजीसी के विनिमय 2018 अनुसार कुलपति पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास दस सालों का प्राध्यापक या प्रोफेसरशिप का अनिवार्य अनुभव होना दोनों सदनों से पारित नियम है। बीआर यादव ने कहा कि ममता चंद्राकर की नियुक्ति राजभवन के आदेश के माध्यम से विवि अधिनियम 2019 के निहित कुलाधिपति के स्वेच्छाधिकार से किया गया है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन में पारित

निर्णय अनुसार राजकीय अधिनियम का उक्त प्रावधान लागू नहीं होता।

प्रोफेसर शिप में 23 दिन कम होने पर कुलपति को हटाया गया

प्रेस वार्ता में श्री यादव ने यह भी बताया कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रो सदानंद शाही को राजभवन द्वारा प्रोफेसरशिप के दस सालों के कार्यानुभव में महज 23 दिनों की कमी होने के करण हटा दिया गया था।

नियमानुसार कार्यकाल पूर्ण

उन्होंने कहा कि ममता चंद्राकर की नियुक्ति विवि अधिनियम 2019 में निहित प्रावधान अनुसार 65 साल की आयु पूरी होने अथवा पांच साल का कार्यकाल पूरा होने तक हुई है। 2 दिसंबर 23 को ममता चंद्राकर 65 वर्ष की हो गई है इसके बावजूद कुलपति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि तत्संबंध में आयु सीमा बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा कोई भी ओदश जारी नहीं किया गया है। बीआर यादव ने कहा कि ममता चंद्राकर का उम्र सीमा 2 दिसंबर 23 को पूरी करने के बाद एक दिन भी कुलपति के पद पर आसीन रहना किसी भी स्थिति में संवैधानिक या नैतिक रूप से सही नहीं है। अनिवार्य योग्यता नहीं रखने के कारण अविलंब उन्हें पद से हटाकर विवि के किसी वरिष्ठ प्राध्यापक को प्रभारी कुलपति नियुक्त कर नवीन कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

प्रमाणित दस्तावेज लेकर जाएंगे हाईकोर्ट

राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेनि शिक्षक बीआर यादव ने बताया कि कुलपति की नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों को प्राप्त करने उन्हें राजभवन तक दौड़ लगानी पड़ी। जनवरी में उनके आवेदन पर संगीत विवि ने कोई जवाब नहीं दिया जिसके बाद उन्होंने राजभवन का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद उन्हें 28 मार्च को आरटीई से मांगी गई जानकारी मिल पाई। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों से स्पष्ट पता चलता है कि ममता चंद्राकर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पारित निर्णय, यूजीसी के अधिनियमों और संगीत विवि के अध्यादेशों की अनदेखी की गई है। ममता चंद्राकर पर मामले को अन्य माध्यम से भटकाने का आरोप लगाते हुए बीआर यादव ने कहा कि राजभवन में साक्ष्य प्रस्तुत कर शिकायत बाद, कलेक्टर को पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हाईकोर्ट में मामला पेश किया जाएगा।

खनिज विभाग ने वसूला 77 करोड़ 77 लाख का राजस्व

दुर्ग। जिले से खनिज महकमा ने गत वित्तीय वर्ष में कुल 77 करोड़ 77 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग को कुल 87 करोड़ 46 लाख रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य मिला था। जिस लिहाज से विभाग को प्राप्त लक्ष्य का 89 प्रतिशत राजस्व वसूली करने में सफलता मिली।

विभाग ने वर्ष 2023-24 में अवैध खनिज परिवहन के वर्ष 2022-23 की तुलना में अधिक प्रकरण दर्ज किए, इसके बावजूद लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाबी नहीं मिली। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग को 70 करोड़ 71 लाख रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य मिला था, जिसके विरुद्ध 86 करोड़ 17 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई थी जो कुल लक्ष्य का 121.86 प्रतिशत था। विभागीय अमले की माने तो पूर्व में डिया की अनुमति के आधार पर चल रहे अनेक खदानों को सिया से अनुमति के अभाव में खनिज उत्खनन पर काफी समय तक रोक लगी हुई थी, जिससे ये खदान बंद होने से भी राजस्व वसूली इस बार प्रभावित हुई। जिसकी वजह से काफी मशक्कत के बाद भी लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल पाई।

विभाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 की तुलना में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों से अर्थदंड के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवैध खनिज उत्खनन के विभाग ने कुल 22 प्रकरण दर्ज किए, इनमें निराकृत 19 प्रकरणों से अर्थदंड के रूप में 10 लाख 63 हजार 115 रुपए वसूल किया गया। जबकि 3 प्रकरण अभी भी निराकृत होना बाकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 10 लाख 35 हजार 765 रुपए अर्थदंड प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार वित्तीय 2023-24 में अवैध खनिज परिवहन के 164 प्रकरण विभाग ने जिले में दर्ज किया।

इससे अर्थदंड के रूप में 54 लाख 35 हजार 574 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 151 अवैध खनिज परिवहन के प्रकरण दर्ज हुए थे। इससे विभाग को अर्थदंड स्वरूप 46 लाख 60 हजार 170 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।

आरटीई, निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदनों की बाढ़

दुर्ग। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। जिले के 528 निजी स्कूलों में गरीब और मध्यम तपके के बच्चों को प्रवेश दिए जाने आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हुई है। 15 अप्रैल तक आवेदन लिया जाना है। यानी 3 शेष है। कुल 4293 सीटों के विरुद्ध अब तक 12418 ऑनलाइन आवेदन मिल चुके हैं।

निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगाई जाने की प्रक्रिया है। बचे हुए तीन दिनों में आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश की कार्रवाई के संबंध में जारी शेड्यूल के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

डीपीआई के संचालक द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्रवाई, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश व सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा, प्रचार-प्रसार, आवंटन प्रक्रिया, शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा प्रकिया का संपादन किया जाना है। 15 अप्रैल तक आवेदन लेने के बाद 18 अप्रैल से 17 मई तक नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

20 से 30 में तक लॉटरी आवंटन की प्रक्रिया तथा एक से 30 जून के बीच स्कूल दाखिला संबंधी कार्रवाई होगी। इसके बाद द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए 15 जून से शुरू होगा। 15 से 30 जून तक नवीन स्कूलों के पंजीयन संबंधी आवेदन लिए जाएंगे, जिसका सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए आवेदन 1 से 8 जुलाई तक लिया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 528 निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए कुल 77 नोडल बनाए गए हैं। प्रत्येक नोडल के अंतर्गत निजी विद्यालयों की संख्या 4 से 12 तक है। वैसे सभी नोडल अधिकारी प्राय: प्राचार्य ही है। दस्तावेजों का परीक्षण, स्कूलों का सत्यापन की जिम्मेदारी नोडल प्राचार्य पर ही रहती है।

स्कूल बसों की सरप्राइज जांच शिविर 11 बसों में खामी

दुर्ग। यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस का सरप्राइज जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 13 स्कूलों के छात्र-छात्राओं में परिवहन करने वाले 151 बसों का जांच किया गया है।

वाहन की जांच शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है। जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनों का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया। जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किंग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, एक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है कि नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा बिना स्पीड गर्वनर 03, बिना अग्नि शमन 05, बिना वायपर 01, बिना इंडीकेटर 01, बिना कैमरा 01 कुल 11 स्कूली बसों पर चालान करते हुए 8500 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया।

महादेव सट्टा भूपेश बघेल के इशारे पर ही चल रहा था- रामविचार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी के कार्यकाल में हुए दस वर्ष में हुए कार्यों को गिनाते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद देश की दशा व दिशा दोनों बदलेगी।

रायगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा दस वर्षों के दौरान किये गए कार्यों को ब्यौरा देते हुए कहा कि जनता एक बार फिर से मोदी की गारंटी को लेकर वोट डालने वाली है।

उन्होंने विकास कार्यों को ब्यौरा देते हुए यह भी कहा कि संकल्प पत्र में जो कहा था वह किया और इस बार नये संकल्पों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जिसमें किसानों, युवाओं,

महिलाओं तथा मध्यम वर्गों के लिये कई वादे किये गए हैं।

इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चैधरी ने भी मोदी के विजन को लेकर अपनी बात रखे और बताया कि रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में रूके हुए कामों को न केवल गति मिलेगी बल्कि सडकों की हालत भी सुधरेगी।

उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में सडकों के कायाकल्प को लेकर पहले से ही बजट में प्रावधान रखा गया है और लोकसभा चुनाव के आचार सहिता खत्म होनें के बाद भी निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा।

पत्रकार वार्ता के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप मामले में जमकर घेरा और लगातार नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गालियां व घटिया बयानबाजी को लेकर भी बात कही।

उन्होंने कहा कि आज मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिसमें पिछले दस सालों में हमारे देश की नही बल्कि दुनिया के लोकप्रिय नेता मोदी जी के कार्यकाल का हमने लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और आगे पांच साल में हमारी सरकार को करने वाली है उसके बारे में हमने इसमें रखा है। साथ ही साथ आज नामांकन रैली भी है।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से चुनाव जीताने की भी अपील की और फिर से मोदी सरकार बनाने की बात कही।

महादेव सट्टा एप के मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि महादेव सट्टा एप तो भूपेश बघेल के इशारे पर ही चल रहा था। जो-जो माल खायें है सब नाम ले रहा है भूपेश बघेल का, जिसमें कुछ अंदर हैं कुछ बाहर घुम रहे। लेकिन सब के पीछे तमाम एजेंसी लगी हुई है। जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो कहीं भी रहे वो बचने वाले नही। कांग्रेस की परंपरा रही है किसी को भी अपमानित करना।

समाम को अपमानित करना, लोगों को गालियां देना और गाली देते-देते मोदी जी को जीतने गालियां देंगे कांग्रेस उतनी रसातल की ओर जाएगी।

किराये के मकानों में संचालित हो रहे शहर के कई आंगनबाड़ी

रायगढ़। औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाता, कला व संस्कृति का धनी रायगढ़ जहाँ लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबपतियों के कारोबार चल रहे हैं वहाँ नौनीहालों की अनदेखी समझ से परे है।

शहर में लगभग एक सौ साठ आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं जिसमें 95 आंगनबाड़ी केंद्र किराये के मकानों में चल रहे हैं बाकि शासकीय भवनों में हैं। शासकीय भवनों में पाँच भवन जर्जर स्थिति में हैं। रायगढ़ शहर के संजय नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन इतना खराब हो चुका है कि छत का प्लास्टर गिरने लगा है ऐसी हालत में छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ कैसे रखा जा सकता है।

आँबा कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्षा अनीता नायक ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि निगम द्वारा जमीन और भवन की स्वीकृति हुई थी। नक्शा खसरा भी जमा हो गया है, परन्तु आज तक नहीं बन पाया। भवन और पर्याप्त जगह के अभाव में बच्चे व हितग्राही शासन की योजनाओं तथा कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। सवाल उठता है कि रायगढ़ शहर के आंगनबाड़ी केंद्र आखिर कबतक किराये के मकानों में संचालित होते रहेंगे?

जो कुछ गिनती के भवन हैं वह भी जर्जर हालत में हैं इनका मरम्मत क्यों नहीं किया जा रहा है? एक तरफ जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों और महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील है, तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित विभाग और नेता गण चुप्पी साधे तटस्थ नजर आ रहे हैं।

85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक और निशक्तजनों को होम वोटिंग की सुविधा

मुंगेली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि बिलासपुर लोकसभा निर्वाचन के लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी अधिकारियों को जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, इसे गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें।

उन्होंने कहा अधिकारी अपने कार्यस्थल में निर्धारित समय पर उपस्थित रहें। निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही एवं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों में पेयजल, छाया सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग के लिए भी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठजन और ऐसे दिव्यांगजन जो मतदान केंद्र जाने में अक्षम हों, उन्हें होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अनिवार्य सेवाओं में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। उन्होंने होम वोटिंग, पोस्टल बैलेट वोटिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वीप कार्यक्रम के तहत किए जा रहे मतदाता जागरूकता गतिविधियों की जानकारी ली और प्रत्येक

पोलिंग बूथ में मतदाताओं के घर-घर जाकर सात मई को लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्वीप सेल के नोडल अधिकारी को मतदाता जागरूकता के लिए विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे गतिविधियों की मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

करोड़ों का धान घोटाला होने की आशंका, कई की संलिप्तता..!

रायगढ़। धान खरीदी के दौरान बोगस खरीदी और फर्जी लोन के मामले सामने आए, लेकिन प्रशासन चुप रहा। खरीदी पूरी होने के बाद भौतिक सत्यापन कराया गया, लेकिन अफसर सब कुछ छिपा गए। अब उठाव के आखिरी दिनों में राजपुर समेत दर्जन भर समितियों में शॉर्टेज आ चुका है। इसकी भरपाई कराने के लिए अब अधिकारी मिलरों के डीओ बिकवा रहे हैं।

रायगढ़ जिले में इस साल 53.91 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसमें से 50 हजार क्विंटल से अधिक धान अब भी केंद्रों में पड़ा दिखाई दे रहा है। अभी किसी भी केंद्र में धान नहीं है लेकिन उठाव हो रहा है। बोगस खरीदी के कारण दर्जनभर समितियों में भारी मात्रा में धान रिकॉर्ड में बचा हुआ है। अब इस बोगस खरीदी की जानकारी को छिपाकर भरपाई कराने का काम अधिकारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के रायगढ़ प्रवास के पूर्व ही सभी केंद्रों को जीरो शॉर्टेज करने की तैयारी है। चाहे किसी भी तरह हो, समिति में धान की भरपाई कराई जानी है। जिन मिलरों के डीओ काटे जा चुके हैं, उनकी डील समिति प्रबंधकों से कराई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि खरीदी के तुरंत बाद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने उपार्जन केंद्रों का सत्यापन करने का आदेश दिया था। खाद्य विभाग के मार्गदर्शन में टीम भी बनी, लेकिन कैसा भौतिक सत्यापन हुआ किसी को नहीं पता। बोगस खरीदी का पता उसी समय चल गया था, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग कलेक्टर को नहीं की गई। करीब 15 करोड़ के घोटाले को छिपाया गया।

कई लोगों की है संलिप्तता

इस बार राजपुर, लैलूंगा, कापू, लिप्ती, सिसरिंगा, लारीपानी, लिबरा, घरघोड़ा, कोड़ासिया, खडगांव आदि केंद्रों में बोगस खरीदी हुई और ओडिशा का धान खपा है। फरवरी में ही धान कम मिला था, लेकिन तब कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्हीं केंद्रों में शॉर्टेज आ रहा है। अब भी जांच और कार्रवाई नहीं हो रही। गड़बड़ी को छिपाने के लिए ताबड़तोड़ तरीके से डीओ में गड़बड़ी की जा रही है।

1900 से 2200 में बिक रहे डीओ

जिन केंद्रों में मिलरों के डीओ जारी हो गए हैं, लेकिन धान नहीं है, वहां डीओ को बिकवाया जा रहा है। समिति प्रबंधक ही बोगस खरीदी को एडजस्ट करने के लिए मिलरों के डीओ 1900-2200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद रहे हैं। धान की कीमत 3100 रुपए है मतलब करीब 1000 रुपए प्रति क्विंटल की अवैध कमाई हो रही है जो कई स्तरों में बंट रही है।

रेलवे स्टेशन के भीतरी और बाहरी क्षेत्र में हाईटेक सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगेंगे

बिलासपुर। पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा रेलवे सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस एवं रेंज के रेल लाईन से जुडे जिले बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं सक्ती के अधिकारियों की बैठक ली गई।

बैठक से जुड़े एजेण्डा बिन्दुओं पर प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया, तदुपरांत जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा रेलवे सुरक्षा संबंधी समस्या और सुझावों से अवगत कराया गया।

पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला द्वारा रेलवे स्टेशनों में आर.पी.एफ. द्वारा लगवाये जा रहे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों को स्थापित करने की जानकारी ली गई व कैमरों को लगवाने के समय इसकी पोजिशनिंग के लिए जिला पुलिस का सहयोग लेने निर्देशित किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला पुलिस बल, आर.पी.एफ., जी.आर.पी. तथा जिला प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रील कराने निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षकों को आर.पी.एफ एवं जी.आर.पी. के साथ रेलवे सुरक्षा से संबंधित मुद्दे तय कर इसकी समीक्षा हेतु प्रति माह बैठक आयोजित करने निर्देशित किया।

रेलवे स्टेशनों के वाहन पार्किंग में वर्षों से पड़े लावारिश वाहनों के नियमानुसार निराकरण के लिए स्थानीय पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये गये। जिला बिलासपुर रेलवे स्टेशन में लावारिश 151 वाहनों की विधिवत नीलामी की कार्यवाही की प्रक्रियाधीन होने संबंधी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा दी गई, जिसे शीघ्र पूर्ण कराने तथा चोरी की प्रापर्टी की जांच के दौरान रेलवे स्टेशनों में खड़े वाहनों की जांच रेण्डमली कर लेने संबंधी निर्देश पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिये गये।

फ्लैग मार्च के माध्यम से आचार संहिता अनुपालन व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

गरियाबंद। जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर दीपक कुमारअग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के नेतृत्व में शनिवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कीसंयुक्त टीम ने गरियाबंद शहर में फ्लैग मार्च निकाला। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष, निर्भीक और भयमुक्त चुनाव करवाने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकालकर शांति और एकजुटता का संदेशदिया। फ्लैग मार्च के माध्यम से जिले केवरिष्ठ अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर आचार संहिता अनुपालन और चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय सहितप्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

दुर्ग से विशाखापट्टनम तक चलेगी वंदे मातरम एक्सप्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि दुर्ग से विशाखापट्टनम तक अब नई वंदे .भारत एक्सप्रेस चलने वाली है।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेन आचार संहिता खत्म होने के बाद जून के अन्त तक चल सकती है। सूत्रों का दावा है कि इसका समय भी तय कर दिया गया है। इस ट्रेन के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है।

लंबे समय से थी आंध्रा समाज की मांग

इस ट्रेन के चलाने को लेकर कई वर्षो से आंध्रा समाज मांग कर रहा है। पिछले दिनों खबर आई कि ये ट्रेन चलने वाली है, लेकिन किसी कारण से ये ट्रेन शुरू नहीं हो सकी, जिसके बाद समाज का एक प्रतिनिधि मंडल रायपुर डीआरएम के पास गया था। लेकिन वहां समाज के लोगों के साथ डीआरएम ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, जिसके बाद समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी। अब उनके लिए ये खुशखबरी है कि ट्रेन का संचालन जल्द शुरू होने वाला है।

8.30 घंटे में पहुंचेगी विशाखापट्टनम

रेलवे सूत्रों के मुताबिक दुर्ग से यह ट्रेन सुबह 6 बजे निकलेगी और दोपहर 2.30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। दोपहर 3.15 को विशाखापट्टनम से छूटेगी तथा साढ़े आठ घंटे में 565 किलोमीटर की दूरी तय कर रात 11.50 को दुर्ग स्टेशन पहुंचेगी।

माता कर्मा त्याग, तपस्या एवं भक्ति की प्रतिमूर्ति-इंद्रकुमार

नवापारा-राजिम। समीपस्थ ग्राम परसदा में भक्त माता कर्मा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ स्वजातीय बंधुओ के द्वारा माता कर्मा की पूजा अर्चना कर खिचड़ी का भोग लगाया गया गया। तत्पश्चात भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसे समाज की युवतियां एवं महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर साहू समाज भवन से निकलकर बाजार चौक, भाटापारा, घासीदास चौक, गायत्री चौक गौरा चौक, शीतला चौक से भ्रमण करते हुए वापस साहू समाज भवन में पहुंची। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने कहा कि साहू समाज एक विस्तृत समाज है। हमें गर्व होना चाहिए हमारे कुलदेवी भक्त शिरोमणि भक्त माता कर्मा है। माता कर्मा का जीवन त्याग, तपस्या और प्रभु की

सेवा करना रहा है। इसलिए माता कर्मा त्याग, तपस्या एवं भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। ग्रामीण साहू समाज के जिलाध्यक्ष देवनाथ साहू ने कहा कि भक्त माता कर्मा ने अपने भक्ति के बल पर भगवान को अपने भक्ति की डोर में बांधकर भक्ति भाव का परिचय दिया। हम सभी माता कर्मा के त्याग, तपस्या एवं बलिदान को ग्रहण करें तथा मर्यादित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।

तहसील साहू समाज के अध्यक्ष ब्रह्मानंद साहू ने कहा कि माता कर्मा से हमें त्याग और धार्मिकता की शिक्षा मिलती है। भक्त माता कर्मा ने शोषित एवं पीड़ितों के लिए जो संघर्ष किया उससे समाज गौरवान्वित है। कार्यक्रम को खोरबाहरा राम साहू, परदेशी राम साहू ने भी सम्बोधित किया।

कार्यक्रम के अंत सभी अतिथियों को गमछा (स्कार्फ) व श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। वहीं रात्रि में माँ की प्रेरणा सुआ नृत्य आरंग की प्रस्तुति हुई।

जंगलों के अंदर चल रहीं हैं एम.डी. डिस्टिलरीज

पुलिस द्वारा 50 क्विंटल महुआ पास बरामद, वन विभाग की लापरवाही उजागर

सरायपाली। वनों की सुरक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वन विभाग को सौंपा गया है । वनों को और हरित भरित करने सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये सिर्फ पौधारोपण में ही खर्च किये जाते हैं। इन पौधों को पानी देने व सुरक्षित ढंग से बड़ा करने के लिए अलग से फंड की व्यवस्था सरकार करती है । सुरक्षित जलवायु तथा वातावरण हेतु स्वस्थ वनों का होना अत्यंत आवश्यक है । संतुलित पर्यावरण में वनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है ।

वनों की रक्षा व सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा अलग अलग बीट बनाकर बीट प्रभारी नियुक्त किये गये हैं ताकि वे जंगलों के अंदर वन्य प्राणियों व जंगलों की सुरक्षा अंदर तक जाकर कर सकें। जंगलों में लकड़ियों की अवैध कटाई, चोरी, वनों को आग से सुरक्षा, लकड़ी चोरों से वनों को सुरक्षित रखे जाने के लिए अलग अलग क्षेत्र का निर्धारण कर डिप्टी रेंजरों की नियुक्ति की गई है ताकि जंगलों को सुरक्षित रखा जा सके ।

जंगलों में किसी भी प्रकार का अवैध कार्य व जंगलों का कोई दुरुपयोग न कर सके इस हेतु इनकी रक्षा व सुरक्षा के लिए भारी भरकम अमलो की नियुक्ति भी की गई है ताकि वे सरकार के उद्देश्यों को पूरा कर सकें । किंतु इतनी सुविधाओं, आर्थिक सहयोग व खर्च तथा भारी भरकम अधिकारियों-कर्मचारियों की फौज होने के बावजूद क्या वन विभाग सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है ? क्या जंगलों को सुरक्षित रख पा रहा है ? क्या अवैध लकड़ी कटाई को रोक पा रहा है ? क्या जंगलों में विचरण कर रहे वन्य प्राणियों को सुरक्षा व सुविधा दे पा रहा है ? क्या जंगलों में होने वाले अवैध गतिविधियों को रोका जा रहा है ? क्या जंगलों के संवर्धन व संरक्षण के लिए प्राप्त होने वाली राशि का वनों की रक्षा व सुरक्षा में खर्च हो रहा है ? ऐसे अनेक सवाल हैं किंतु ऐसे सवालों का सही जवाब वन विभाग से मिल माना संभव नही नजर आ रहा है।

वन विभाग व उनके अधिकारी-कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति कितने मुस्तैद रहते हैं यह सिंघोड़ा पुलिस द्वारा पिछले दिनों जंगल के अंदर एक नही दो बार की गई कार्यवाही से स्पष्ट हो गया है । सिंघोड़ा पुलिस द्वारा बलेन्डा के जंगलों में 50 क्विंटल महुवा लहान पास जप्त करने की कार्यवाही ने वन विभाग की कार्यशैली व कर्तव्य के प्रति बरती जा रही लापरवाही को सामने ला दिया है ।

छत्तीसगढ़ के पिरपोटी टमाटर का जीआई टैग के लिए पंजीयन

■ इसकी चटनी का स्वाद है लाजवाब

■ पिरपोटी टमाटर की फसल विलुप्त होने के कगार पर

धमतरी। सरगुजा के जीराफूल व नगरी के दुबराज चावल के बाद अब नगरी के ही पिरपोटी टमाटर को राज्य की तीसरी फसल के रूप में नई दिल्ली से कृषक पौधा किस्म के लिए पंजीयन किया है। इसे जल्द ही जीआई टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशंस) मिलने की संभावना है, जो धमतरी जिला के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि यह चाव का टमाटर है और स्वाद भी चटपटा है।

पिरपोटी टमाटर की फसल विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन इस टमाटर के फसल को नगरी ब्लाक के गुहाननाला के किसान बंशीलाल सोरी आज भी सहेजकर रखा है, उनके बाड़ी में साल के छह माह उत्पादन होता है। यह टमाटर पूरे प्रदेश में चाव का टमाटर है और स्वाद भी काफी चटपटा है, जो दिखाई देते ही जी ललचा जाता है। लोग बाजार में दिखते ही इसे खरीद लेते हैं, क्योंकि इसके चटनी के सामने सभी चटनियों का स्वाद फेल है।

ऐसे पिरपोटी टमाटर के विलुप्त उत्पादन को बंशी लाल सोरी ने कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित प्रदर्शनी में लगाया था, जो कृषि वैज्ञानिक व अधिकारियों को भा गया। इस टमाटर की पूरी जानकारी लेकर शासन को भेजा था, इसके आधार पर नई दिल्ली द्वारा किसान बंशीलाल सोरी के नाम पर पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार अधिनियम 2001 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वह उक्त पौधा किस्म के अधिकार का हकदार है।

आठ जनवरी 2024 को पंजीकरण पर मुहर लगाई गई है। पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के तहत नई दिल्ली के द्वारा पंजीयन किया गया है। जल्द ही इसे जीआई टैग मिलने की संभावना है। पौध किस्म संरक्षण के तहत धमतरी जिले में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला छोटे आकार का यह देशी पिरपोटी टमाटर है।

अपने बाड़ी में पिरपोटी टमाटर लगाने वाले किसान बंशीलाल सोरी ने बताया कि उनके घर के बाड़ी में बचपन से ही दो से तीन डिसमिल में इसकी खेती करते हैं। पहले उनके माता-पिता करते थे, अब वह स्वयं इसे सहेजकर हर साल उगाते हैं। बाड़ी में चार से पांच पेड़ लगाते हैं, जो पूरी तरह से आर्गेनिक है। जुलाई में बीज छिड़कते हैं, तैयार होकर जनवरी-फरवरी से फल देना शुरू करता है और मार्च-अप्रैल तक फल देता है। 99 प्रतिशत बीज सुरक्षित रहता है, जमीन में कहीं भी उग जाता है। छत में भी यह टमाटर लगाया जाता है।

चटनी और सब्जी के लिए उपयोग

फार्मिंग टमाटर के स्वाद से काफी बेहतर होता है। इसे चटनी और सब्जी के लिए उपयोग करते हैं, इस टमाटर के स्वाद के लिए दूसरा कोई अन्य टमाटर नहीं है। इस टमाटर के किस्म का पंजीयन होने के बाद आसपास के किसानों व लोगों को इस टमाटर की खेती के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि यह टमाटर सालोंसाल सुरक्षित रहे। एक बार बाड़ी में इस टमाटर के लगने के बाद लोगों को बाजार से हाईब्रिड टमाटर खरीदने की जरूरत न पड़े। लोगों के रुपये बचेंगे साथ ही उन्हें सब्जी में चटपटा स्वाद मिलेंगे।

औषधी गुणों का भी पर्याय

कृषि विभाग धमतरी के एफएल पटेल उप परियोजना संचालक धमतरी ने बताया कि नगरी के पिरपोटी टमाटर को पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के तहत नई दिल्ली के द्वारा पंजीयन किया गया है, जो जिले के लिए गर्व की बात है। जल्द ही पिरपोटी टमाटर को जीआई टैग मिलने की संभावना है। इससे वनांचल क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। पिरपोटी टमाटर अपने न केवल खट्टा स्वाद के लिए बल्कि कई पोषक एवं औषधी गुणों का भी पर्याय है।

सरकार के तीन माह के कार्यकाल में राज्य में लौटी खुशहाली

कोरबा। प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव सरकार के 100 दिन पूरे होने पर श्रम एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि बीते पांच साल में कांग्रेस सरकार की वादाखिलाफी से हर वर्ग में असंतोष का माहौल था, भाजपा सरकार के इन तीन माह में ही आम जनता के बीच खुशहाली लौटी है। विष्णुदेव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को इन 100 दिन में ही पूरा किया है।

मंत्री देवांगन ने कहा कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल, महतारी वंदन योजना, 18 लाख पीएम आवास योजना की सौगात जनता को मिल चुकी है। जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभागों के माध्यम से भी योजना का लाभ लोगों को मिलने लगी है। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री देवांगन ने कहा कि कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा की जीत पक्की है। सरोज पूरे छत्तीसगढ़ की बेटी है, उनके जैसा सशक्त नेतृत्व कोरबा को मिलने वाला है। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर, भाजपा जिलाध्यक्ष डा राजीव सिंह, बिहार से आए एमएलसी देवेश, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम हितानंद अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, सह प्रभारी पवन सिन्हा समेत भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जयसिंह को भाजपा में लेने का सवाल नहीं उठता

नेता प्रतिपक्ष डा चरण दास महंत द्वारा पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भाजपा में शामिल करने के लिए दबाव बनाए जाने के सवाल पर मंत्री देवांगन ने कहा कि वे कई तरह के आरोप में घिरे हुए हैं। उन्हें लेने का सवाल ही नहीं उठता है। हार को देखते हुए अब कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, सब को पता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की नैया पूरी तरह से डूब जाएगी।

डीएमएफ में हो रही थी अनियमितता तो सांसद क्यों थी मौन

नगर निगम के श्यामनगर और इंदिरानगर में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत बीते पांच साल से संसदीय क्षेत्र से गायब रही और जनता ने उन्हें देखा ही नहीं। कोरबा में डीएमएफ में अरबों का घोटाला हुआ और सांसद ने कभी विरोध नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि ज्योत्सना महंत की भी सहमति थी।

उन्होंने कहा कि पांच साल में सांसद ने कोरबा में एक भी विकास का ईंट तक नहीं रखा। पांच साल में कोरबा को कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का ही काम किया है।

19 लाख के धान का गबन, समिति अध्यक्ष व केंद्र प्रभारी को तीन साल की कैद

सक्ती। लगभग दस साल पहले धान खरीदी में 19 लाख रूपये की गड़बड़ी व धोखाधड़ी कर गबन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती गंगा पटेल ने समिति के प्रभारी अध्यक्ष व धान खरीदी प्रभारी को तीन तीन साल सश्रम कारावास और पांच पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि एक आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2013 - 14 में दर्राभांठा सेवा सहकारी समिति के किसानों ने शिकायत की थी कि उनके द्वारा समिति को विक्रय किए गए धान के रकम का भुगतान नहीं हुआ है तथा धान की अफरातफरी की जा रही है। जिस पर तत्कालीन खाद्य अधिकारी विमल दुबे, जिला विपणन अधिकारी के पी कर्ष, उप पंजीयक सहकारी संस्था वीके तिवारी के द्वारा संयुक्त जांच दल बनाकर सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया। जिसमें मौके पर 1955 बोरी धान का तौल किया गया। इन बोरियों में40 किलोग्राम के स्थान पर 29 किलोग्राम धान मिला। उपस्थित किसानों ने बताया कि समिति को बेचे गए धान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जांच दल के द्वारा बारीकी से दस्तावेजों एवं फड़ में मौजूद धान का भौतिक सत्यापन किया गया।

जिसमें सेवा सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू एवं खरीदी केंद्र प्रभारी देवेंद्र साहू एवं उसके पिता गोपाल साहू के द्वारा मिलकर तौल में गड़बड़ी कर 86 किसानों के द्वारा लाए गए 3264 बोरी धान को कंप्यूटर में दर्ज नहीं करने और कुल 19 लाख रुपए का गबन व धोखाधड़ी करने की बात सामने आई। इस संबंध में पंचनामा तैयार कर थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। एएसआई टीडी कोशले ने मामले की विवेचना की और सहकारी समिति दर्राभांठा के प्रभारी अध्यक्ष रामायण साहू, खरीदी केंद्र प्रभारी देवेंद्र साहू तथा उसके पिता गोपाल साहू की संलिप्तता पाई।

तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती गंगा पटेल ने रामायण साहू एवं देवेंद्र साहू को धान खरीदी में गड़बड़ी और गबन के लिए दोषी पाया। उन्हें भादवि की धारा 409 के लिए, तीन तीन वर्ष कारावास एवं पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया । जबकि गोपाल साहू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सक्ती अरविंद कुमार जायसवाल ने पैरवी की ।

बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की भर्ती निरस्त करने हाईकोर्ट का आदेश

प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे

बिलासपुर। बीएड डिग्रीधारी टीचर भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित चयन सूची जारी कर डीएलएड उम्मीदवारों को मौका देने के लिए कहा है. इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है.

बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि वैसे बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए. कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं.

अब काले कोट नही पहनेंगे वकील

भीषण गर्मी के चलते नया गाइड लाइन हुआ जारी...

अंबिकापुर। राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यकारिणी समिति छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भीषण गर्मी से अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने की बाध्यता से राहत हेतु 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक छूट प्रदान की गई है। संशोधित अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(जीजी) के तहत अधिवक्ताओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाकों के नियमों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों में उपस्थित होने वाले वकील ऐसा पोशाक पहनेंगे, जो शांत और गरिमामय होगा। जिसके तहत -

अधिवक्ता

(ए) एक काले बटन वाला कोट, चपकन, अचकन, काली शेरवानी और एडवोकेट गाउन के साथ सफेद बैंड।

(बी) एडवोकेट गाउन के साथ एक काला खुला ब्रेस्ट कोट, सफेद शर्ट, सफेद कॉलर, कठोर या मुलायम और सफेद बैंड।किसी भी स्थिति में जींस को छोड़कर लंबी पतलून (सफेद, काला, धारीदार या ग्रे) धोती पहनें। बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय या सिटी न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों में बैंड के बजाय काली टाई पहनी जा सकती है।

महिला वकील

(ए) काली पूरी बांह की जैकेट या ब्लाउज, सफेद कॉलर सख्त या मुलायम, सफेद बैंड और एडवोकेट्स गाउन के साथ।

सफेद ब्लाउज, कॉलर के साथ या बिना, सफेद बैंड के साथ और एक काले खुले ब्रीड कोट के साथ। या छ्ठ

(बी) साड़ी या लंबी स्कर्ट (सफेद या काला या कोई हल्का या हल्का रंग बिना किसी प्रिंट या डिजाइन के) या फ्लेयर (सफेद, काला या काली धारीदार या ग्रे) या पंजाबी पोशाक चूड़ीदार कुर्ता या सलवार कुर्ता दुपट्टे के साथ या बिना दुपट्टे के (सफेद या काला) या काले कोट और बैंड के साथ पारंपरिक पोशाक। *- उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होने के अलावा अधिवक्ताओं का गाउन पहनना वैकल्पिक होगा या उच्च न्यायालयों में.

* सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर गर्मियों के दौरान काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं है। उपरोक्त संशोधित नियम- के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, गर्मियों के दौरान काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं है।

उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायपालिका को 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक नियम का पालन करने कहा गया है। सचिव स्टेट बार कांउसिल ऑफ छत्तीसगढ़ अमित कुमार वर्मा के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में भारतीय विधिज्ञ परिषद नई दिल्ली द्वारा ड्रेस कोड के संबंध में पारित नियम के अधीन धारा 49 (1) (जी) (जी) अंतर्गत अधिवक्ता अधिनियम 1961 के नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा अधिवक्ताओं को ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय न्यायालय में उपस्थिति हेतु कोट पहनने से छूट प्रदान की गई है।

बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी

रायपुर। कांग्रेस में अंतरकलह बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे है। ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें ये सदस्यता दिलाई है।

बता दें कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। वे यहां दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल के नामांकन रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि

कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, इसके चलते कई लोग आज जेल में है। उन्हें साल भर से बेल नहीं मिल रहा है। इससे पहले नामांकन रैली में सैकड़ों लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल भी भाजपा में शामिल हुई हैं।

नामांकन रैली में पहुंचे पूर्व सैनिक विपुल साहू, जोगी कांग्रेस के पाटन से चुनाव लड़ चुकी शकुंतला साहू, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष घनाराम साहू (वर्तमान में भाजपा के सदस्य) के पुत्र सतीश साहू समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा का दामन थामा। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी का गमछा पहनाकर सभी का स्वागत किया।

गौरतलब है कि, भूपेश बघेल पर लगातार कांग्रेस नेताओं ने भेदभाव और उनकी बात न सुनने का आरोप लगाकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और अब भूपेश बघेल के परिवार में भी विवाद नजर आ रहा हैं।

हमारा यह संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र- विष्णुदेव साय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम साय ने कहा, भाजपा का संकल्प भारतीय लोकतांत्रिक के भरोसे, विश्वास बहाली के साथ भारत के भविष्य का सुनहरा रोडमैप है। हमारा यह संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र है। बड़े ही पावन अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे जारी किया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने संकल्प जारी किया था जो पार्टी का विजन डाक्यूमेंट था। जिस पर लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये संकल्प पत्र में जो है वो कभी पूरा भी हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र में देश की जनता से किए वादे को अक्षरश: क्रियान्वित किया। सीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 2024 के संकल्प पत्र में 70 साल की उम्र से ऊपर के किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये की मुफ्त इलाज की सुविधा होगी।

पूर्व सांसद दिनेश कश्यप से राजनाथ ने पूछा, मेरा टिकट दोबारा कट गया

जगदलपुर। बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद और बस्तर में आदिवासी नेता बलरिाम कश्यप के बेटे दिनेश कश्यप का टिकट कटने पर आखिरकार दर्द छलक ही गया।

दरअसल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को बस्तर में चुनावी रैली के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जब दिनेश कश्यप की बारी आई तो उन्होंने फूल देकर स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने जैसे ही उनका हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा, इस बार भी मेरा टिकट कट गया। जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा, चलो कोई बात नहीं, फिर मिलेगा।

भाजपा ने इस बार बस्तर लोकसभा सीट से महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। महेश पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने यहां से अपने वर्तमान सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का टिकट काटकर कोंटा सीट से लगातार छह बार के विधायक कवासी लखमा को मैदान में उतारा है।

दिनेश कश्यप बस्तर से दो बार चुने गए सांसद

बतादें कि बस्तर के दबंग नेता बलिराम के बेटे दिनेश कश्यप 2011 और 2014 में संसद चुने गए। इससे पहले भी बस्तर सीट में भाजपा का ही कब्जा था। बलिराम कश्यप 1998 से लगातार चार बार जीते थे। बलिराम कश्यप के निधन के बाद 2011 में दिनेश कश्यप सांसद चुने और फिर 2014 में बस्तर की जनता ने पुन: दिनेश कश्यप के रूप में भाजपा को संसद भेजा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139